दैनिक
सनातन वीर
Reg. No. MPHIN/25A3002
राष्ट्रहित, धर्मरक्षा जनसेवा को समर्पित

नगर संस्करण | इंदौर, सोमवार, 09 फरवरी 2026 | वर्ष : 01, अंक : 70, कीमत : 03 रुपए, पृष्ठ : 8

चुनाव में वोट चोरी से भी नहीं है अछूता अमेरिका से हुई डील के खिलाफ अन्नदाता

नई दिल्ली ● एजेंसी

वोट चोरी का मुद्दा इन दिनों कई देशों में चल रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने देश की चुनाव प्रणाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी चुनाव गड़बड़ी हो रही है। आगे कहा कि वोटों की चोरी को लेकर दुनिया भर में अमेरिका का मजाक बन रहा है। ट्रंप ने चुनाव सुधारों की मांग करते हुए सख्त वोटिंग नियम लागू करने की अपील की है। उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं से एक नए विधेयक के समर्थन में खड़े होने को कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर चुनाव प्रणाली को ठीक नहीं किया गया तो देश को नुकसान होगा। उन्होंने "सेव अमेरिका एक्ट" नाम के प्रस्तावित विधेयक का जिक्र किया। यह रिपब्लिकन पार्टी का नया बिल है, जिस पर कांग्रेस में काम चल रहा है। इस बिल का मकसद संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण और मतदान नियमों को सख्त करना है।

नागरिकता का प्रमाण दिखाना अनिवार्य करने की मांगः ट्रंप ने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन के समय हर मतदाता को अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण दिखाना जरूरी होना चाहिए। उन्होंने पहचान पत्र दिखाना भी अनिवार्य करने की बात कही। उनके अनुसार बिना कड़े सत्यापन के चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। प्रस्तावित बिल में भी नागरिकता प्रमाण के साथ व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण की शर्त शामिल है।

सोशल मीडिया पोस्ट में रखीं तीन बड़ी मांगें

ट्रंप ने अपने संदेश में तीन प्रमुख मांगें गिनाईं। पहली, सभी मतदाताओं के लिए पहचान पत्र दिखाना जरुरी हो। दूसरी, वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य हो। तीसरी, डाक से मतदान को अपवाद स्थितियों तक सीमित किया जाए। उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं से इन बिंदुओं के लिए खुलकर लड़ाई लड़ने की अपील की। सेव अमेरिका एक्ट पर कांग्रेस में चर्चा की तैयारी चल रही है। रिपब्लिकन सांसद इसे चुनाव पारदर्शिता से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं विरोधी खेमे की ओर से सख्ती बढ़ने पर मतदाता पहुंच प्रभावित होने की आशंका जताई जा सकती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अमेरिकी राजनीति में तीखी बहस होने के संकेत हैं।

नई दिल्ली ● एजेंसी

केंद्र सरकार दावा कर रही है कि भारत-अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। समझौते से डेयरी उत्पादों, मसालों के साथ-साथ उन अनाजों, फलों-सब्जियों को पूरी तरह बाहर रखा गया है जो देश के किसानों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन किसान संगठन सरकार की इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार ने इस डील में कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे उनके हितों को चोट पहुंच सकती है। किसान 12 फरवरी को इस डील के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुके हैं। किसानों का यहां तक कहना है कि यदि उनके हितों को चोट पहुंचाई गई तो वे एक बार फिर लंबा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने अमेरिका से समझौते में कुछ कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादों को समझौते से बाहर रखने की बात कही है, जबकि भारत-अमेरिकी समझौते में यह बात स्पष्ट की गई है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी कृषि-डेयरी उत्पादों पर नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर कर देगा। किसानों का मानना है कि इस नॉन टैरिफ प्रतिबंधों को हटाने की आड़ में भारतीय बाजार में ऐसे अमेरिकी कृषि-डेयरी उत्पाद भरे जा सकते हैं जो अब तक आयात नहीं किए जा सकते।

किसान नेता की चिंता

किसान नेता डॉ. आशीष मित्तल ने अमर उजाला से कहा कि भारत-अमेरिका की ट्रेड डील अभी अपने अंतिम स्वरुप में सामने नहीं आई है। लेकिन शुरुआती फ्रेमवर्क में ही सरकार ने अपने इरादे जता दिए हैं। उनके अनुसार, फ्रेम वर्क में अमेरिकी उत्पादों पर नॉन - टैरिफ बाधाओं को पूरी तरह हटाने की बात कहकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारतीय बाजार में ऐसी प्रतिबंधित वस्तुएं भी आयात की जा सकेंगी जिन्हें अब तक आयात नहीं किया जा सकता था।

केंद्र सरकार ने क्या कहा

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने किसानों-श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि सरकार डेयरी, पोल्ट्री और मसालों के सेक्टर में अमेरिकी उत्पादों को नहीं आने देगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत अभी भी कृषि उत्पादों के कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसी वस्तुएं जिनका भारत पहले ही आयात करता है, उन्हें ही भारतीय बाजारों में लाने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये उत्पाद भी सशर्त ही बाजार में प्रवेश कर पाएंगे।

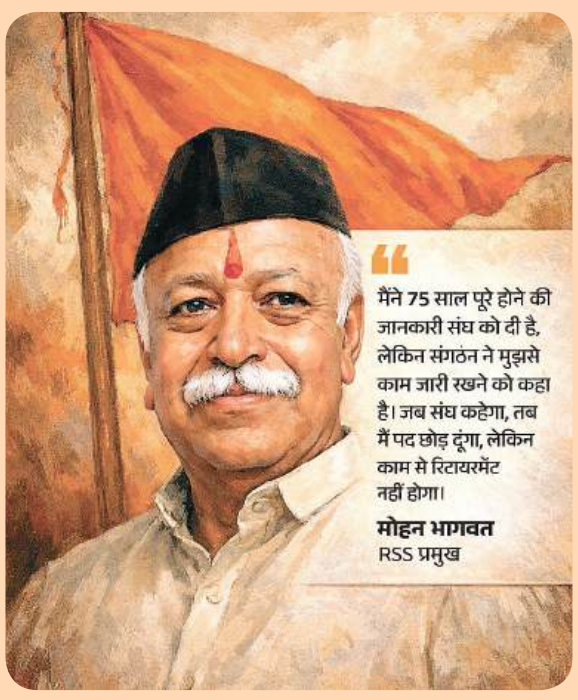

मोहन भागवत बोले- संघ प्रमुख पद छोड़ दूंगा

मुंबई ● एजेंसी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा, तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी पद पर नहीं रहने की परंपरा की बात कही जाती है। RSS प्रमुख ने कहा कि सरसंघचालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू संगठन के लिए काम करता है। वही सरसंघचालक (RSS प्रमुख) बनता है। भागवत रविवार को मुंबई में RSS के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी।

भागवत की स्पीच की बड़ी 9 बातें

- समान नागरिक संहिता (UCC) सभी को विश्वास में लेकर बनाई जानी चाहिए और इससे समाज में मतभेद नहीं बढ़ने चाहिए।
- उम्मीद है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत के हितों को ध्यान में रखकर किया गया होगा और देश को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।
- घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को बहुत काम करना है। पहचान कर निष्कासन की प्रक्रिया होनी चाहिए। यह पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे शुरु हुआ है और आगे बढ़ेगा।
- RSS का काम प्रचार करना नहीं, बल्कि समाज में संस्कार विकसित करना है। जरुरत से ज्यादा प्रचार से दिखावा और फिर अहंकार आता है। प्रचार बारिश की तरह होना चाहिए। सही समय पर और सीमित मात्रा में।
- संघ अपने स्वयंसेवकों से आखिरी बूंद तक काम लेता है। RSS के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, जब किसी को जबरन रिटायर करना पड़ा हो।
- दुनिया में हो रही उथल-पुथल का भारत पर न्यूनतम असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह भारत की पारिवारिक व्यवस्था, सोना बचाने की प्रवृत्ति और परिवार आधारित आर्थिक गतिविधियां हैं।
- RSS को समझने के लिए संघ का हिस्सा बनकर उसका अनुभव लेना जरुरी है। RSS को केवल सतही रुप से समझा जाए, तो उसे गलत तरीके से भी समझा जा सकता है।
- संघ इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्र के विकास में नागरिकों की भूमिका अहम होती है, जबकि सरकारें, राजनीतिक दल और नेता अपनी भूमिका निभाते हैं।
- संघ का सिद्धांत है- व्यक्ति का विकास, ताकि श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण हो सके। RSS की परिकल्पित 'पंच परिवर्तन'- इसमें पारिवारिक जागरण (भजन आदि), पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य शामिल हैं।

बिहार में अश्लील गाने

पटना ● एजेंसी

बिहार सरकार ने 'अश्लील' और 'भाभी-चोली' जैसे फूहड़/दोहरे अर्थ वाले गानों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाया है, और अब ऐसे गानों को सार्वजनिक रूप से सुना/बजाया जाना कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है।

क्या नया नियम हैः बिहार सरकार और बिहार पुलिस ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों, वाहनों (जैसे बस, ट्रक, ऑटो-रिक्शा) या भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अश्लील, फूहड़ या दोहरे अर्थ वाले गाने (जिनमें "भाभी-चोली", "चोली-भौजी" जैसे बोल शामिल हैं) बजाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की जा सकती है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई (जेल तक) संभव है।

कौन दे रहा है यह आदेश : यह दिशा बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे गानों से समाज की संस्कृति, महिलाओं की गरिमा और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस पर सख्ती से रोक लगाई जा रही है।

क्या यह पूरी तरह "गाना बंद" का बैन हैः यह तरीका एक ऐतिहासिक और कानूनी ढांचे पर आधारित है जिसमें पुलिस "अश्लील हरकतों और गीतों" को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत आपत्तिजनक मान सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, और मामला अदालत में जाता है।— बिहार सरकार ने 'अश्लील' और 'भाभी-चोली' जैसे फूहड़/दोहरे अर्थ वाले गानों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाया है, और अब ऐसे गानों को सार्वजनिक रूप से सुना/बजाया जाना कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है।

क्या नया नियम हैः बिहार सरकार और बिहार पुलिस ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों, वाहनों (जैसे बस, ट्रक, ऑटो-रिक्शा) या भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अश्लील, फूहड़ या दोहरे अर्थ वाले गाने (जिनमें "भाभी-चोली", "चोली-भौजी" जैसे बोल शामिल हैं) बजाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की जा सकती है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई (जेल तक) संभव है।

ईरान परमाणु प्रयोग नहीं रोकेगा

ईरान ● एजेंसी

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को अमेरिकी धमकियों को दरकिनार कर दिया। अब्बास अराघची ने साफ किया कि अमेरिका के साथ जारी बातचीत के बावजूद ईरान कभी भी यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से युद्ध की धमकी या क्षेत्र में सैन्य तैनाती से ईरान डरने वाला नहीं है। तेहरान में एक कार्यक्रम में अब्बास अराघची ने कहा कि वॉशिंगटन पर ईरान का भरोसा बेहद कम है और उसे इस बात पर भी संदेह है कि अमेरिका बातचीत को गंभीरता से ले रहा है या नहीं। उन्होंने बताया कि ईरान इन वार्ताओं को लेकर अपने रणनीतिक साझेदार चीन और रूस से भी परामर्श कर रहा है।

अमेरिकी युद्पोतों की तैनाती पर क्यो बोले अराघचीः अराघची ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन पर ईरान का जोर इसलिए है क्योंकि कोई भी देश उसके व्यवहार को निर्देशित नहीं कर सकता। उन्होंने अरब सागर में अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ईरान डरता नहीं है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका ने पिछले वर्ष जून में इस्राइल के साथ हुए 12 दिनों के युद्ध के बाद पहली बार ओमान में बातचीत दोबारा शुरू की है। ईरान इन वार्ताओं में अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना चाहता है और इसके बदले परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कुछ भरोसा बढ़ाने वाले कदमों की पेशकश की बात कर रहा है।

'हमारी ताकत महाशक्तियों को ना कहने की क्षमता'

पश्चिमी देशों और इस्राइल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे ईरान ने खारिज किया है। अराघची ने कहा कि ईरान किसी परमाणु हथियार की तलाश में नहीं है और उसकी असली ताकत महाशक्तियों को 'ना' कहने की क्षमता है। इस बीच इस्राइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। अमेरिका और इस्राइल चाहते हैं कि बातचीत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र संगठनों को समर्थन जैसे मुद्दे भी शामिल हों, लेकिन ईरान ने इन्हें वार्ता का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया है। 'हमारी ताकत महाशक्तियों को ना कहने की क्षमता' पश्चिमी देशों और इस्राइल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे ईरान ने खारिज किया है। अराघची ने कहा कि ईरान किसी परमाणु हथियार की तलाश में नहीं है और उसकी असली ताकत महाशक्तियों को 'ना' कहने की क्षमता है।

बिहार में अनिरुद्धाचार्य की भागवत कथा में भगदड़, वीआईपी कल्चर ने बिगाड़े हालात

मोतिहारी ● एजेंसी

बिहार के मोतिहारी जिले के रक्सौल में भारत–नेपाल सीमा के निकट आयोजित श्रीमद्भागवत कथा महायज्ञ के दौरान रविवार को अचानक अव्यवस्था फैल गई। प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के सत्संग में हजारों-लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से आयोजन स्थल रक्सौल हवाई अड्डा परिसर में भीड़ बेकाबू हो गई।

भीड़ प्रबंधन की कमी से बिगड़े हालातः कथावाचक के मंच पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं का सैलाब पंडाल की ओर उमड़ पड़ा। आयोजन समिति की ओर से भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण मुख्य द्वार पर अत्यधिक दबाव बन गया। इसी दौरान रेलिंग टूट गई और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कार्यक्रम कुछ समय के लिए बाधित हो गया।

घायलों को प्राथमिक उपचार, महिलाएं बेहोशः अफरातफरी के बीच कई श्रद्धालुओं को चोटें आईं। दबाव बढ़ने से दो महिलाएं बेहोश हो गईं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थिति की गंभीरता के कारण कुछ देर तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन रोकना पड़ा।

परिजनों से बिछड़े बच्चे, मदद की व्यवस्था पर सवाल

हंगामे के दौरान कई छोटे बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ गए। आयोजन स्थल पर हेल्प डेस्क या लॉस्ट एंड फाउंड जैसी कोई व्यवस्था नहीं होने से माता-पिता बच्चों की तलाश में भटकते नजर आए। श्रद्धालुओं ने इतने बड़े धार्मिक आयोजन में न्यूनतम सहायता व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई।

वीआईपी व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं में रोष

आम श्रद्धालुओं का गुस्सा वीआईपी व्यवस्था को लेकर भी सामने आया। लोगों का कहना था कि चंदा वसूली के बावजूद पंडाल में केवल अधिक राशि देने वालों को अलग सुविधा और प्राथमिकता दी गई, जबकि आम भक्तों को धक्कों का सामना करना पड़ा, जिससे अव्यवस्था और बढ़ती चली गई।

गंदगी और गंदा पानी नाले में छोड़ने पर कार्रवाई

इंदौर में नगर निगम ने अलग-अलग कंपनियों पर लगाया 1 लाख 80 हजार का जुर्माना

इंदौर ● संवाददाता

पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर निगम लगातार औद्योगिक इलाकों में दौरा और चालानी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में झोन क्रमांक 17 और झोन क्रमांक 3 में आने वाले सांवेर रोड और पोलोग्राउंड स्थित औद्योगिक इलाकों में नालों में गंदगी और अपशिष्ट पानी छोड़ने वाली औद्योगिक इलाकयों पर चालानी कार्रवाई की गई।

झोन क्रमांक 17 में आने वाले सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में कार्रवाई की गई। झोनल अधिकारी नरेंद्र कुरील ने बताया कि रविवार को सांवेर रोड स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा कचरा, गंदगी और अपशिष्ट जल सीधे नाले में छोड़ा जा रहा था। जिसके चलते इन पर कार्रवाई की गई है।

- ललित नमकीन पर 50 हजार रुपए
- मेघा पॉलिमर पर 35 हजार रुपए
- गीतिका प्लास्टिक पर 30 हजार रुपए
- उषा ऑर्गेनिक पर 25 हजार रुपए

नगर निगम ने यहां पर 1 लाख 40 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान झोनल अधिकारी नरेंद्र कुरील, सीएसआई आशीष कापसे, उपयंत्री सिद्धांत मेहता सहित विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

इधर, झोन क्रमांक 3 में आने वाले पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। झोनल अधिकारी राज ठाकुर ने बताया कि निगम कमिश्नर के आदेश पर झोन 3 के वार्ड 57 में कार्रवाई की गई इनमें -

- सायनों फार्मा कंपनी द्वारा ईटीपी (ETP) का उचित संचालन नहीं किए जाने पर 30 हजार का चालान किया गया।
- कोहिनूर इलास्टिक द्वारा सीवर लाइन में सीधे अपशिष्ट जल छोड़े जाने पर 10 हजार की चालानी कार्रवाई की गई।

यहां कुल 40 हजार की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान झोनल अधिकारी राज ठाकुर, सीएसआई राजेंद्र बेगा एवं ड्रेनेज विभाग की टीम उपस्थित रही। निगम अधिकारियों ने औद्योगिक इलाकों को आगामी 2 दिन के अंदर अपशिष्ट जल प्रबंधन सिस्टम को ठीक करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

दलित हिंदू नेता मनोज परमार ने दिखाई मानवता की मिसाल

सड़क हादसे में फंसे मुस्लिम परिवार की बचाई जान

भीलवाड़ा (राजस्थान) / इंदौर। राजस्थान के भीलवाड़ा से इंदौर जाते समय मानवता और भाईचारे की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई। दलित हिंदू नेता मनोज परमार ने सड़क दुर्घटना में फंसे एक मुस्लिम परिवार की जान बचाकर समाज में आपसी सद्भाव का मजबूत संदेश दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यात्रा के दौरान रास्ते में एक कार पलटी हुई दिखाई दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मनोज परमार तुरंत अपनी गाड़ी से उतरे और बिना किसी देरी के दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। उन्होंने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए गाड़ी में फंसे पूरे मुस्लिम परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा अनहोनी टल गई।

मदद पाने वाले परिवार ने बताया कि वे अजमेर शरीफ के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में टक्कर लगने से उनकी कार पलट गई। अचानक हुए इस हादसे में वे बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन समय पर मिली सहायता से सभी की जान बच सकी।

इस मानवीय कार्य के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मनोज परमार की खुले दिल से सराहना की। यह घटना यह साबित करती है कि धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर इंसानियत होती है, और संकट की घड़ी में एक-दूसरे का साथ देना ही सच्चा धर्म है।

मनोज परमार का यह कार्य समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो आपसी सौहार्द, भाईचारे और मानवता के मूल्यों को और मजबूत करता है।

भाजपा नेता की गुंडागर्दी , युवकों के सिर फोड़े, स्कॉर्पियो तोड़ी

इंदौर में समझौते के 20 दिन बाद फिर भड़का विवाद

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर के राऊ इलाके में रविवार सुबह भाजपा युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया।

आरोपियों ने न केवल युवकों के साथ मारपीट की, बल्कि उनकी स्कॉर्पियो कार के कांच भी चकनाचूर कर दिए। घायल युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, हमलावर की पहचान भाजपा युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष वेदांत तिवारी के रूप में हुई है। पीड़ित प्रखर शर्मा और नयन बाफना (सुदामा नगर) सुबह कैट रोड स्थित एक कैफे से चाय पीकर अपनी स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। इसी दौरान वेदांत तिवारी, समीर शर्मा और आदित्य ने उनका पीछा किया और बीच रास्ते में रोककर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर रंजिश चली आ रही है।

पुलिस पर भारी पड़ा 'सियासी दबाव'

घटना के बाद घायल युवक जब राऊ थाने पहुंचे, तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आरोप है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव के चलते पुलिस शुरुआत में FIR दर्ज करने से कतराती रही। हालांकि, जब मामला बढ़ा और थाने पर हंगामा शुरू हुआ, तब जाकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया।

यह पहली बार नहीं है जब वेदांत और उसके साथियों ने इन युवकों को निशाना बनाया हो। करीब 20 दिन पहले महूनाका चौराहे पर भी इन युवकों को घेरने की कोशिश की गई थी। उस वक्त युवक कार भगाकर निकलने में कामयाब रहे थे। मामला छत्रीपुरा थाने तक पहुंचा था, लेकिन तब दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था। इसी समझौते का नतीजा रहा कि आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने दोबारा हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

श्री ओखलेश्वर धाम में विशाल भंडारे का आयोजन

इंदौर। श्री ओखलेश्वर धाम के पावन सान्निध्य में रविवार, 8 फरवरी 2026 को विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे हुआ, जो प्रभु की इच्छा तक निरंतर चला। इस अवसर पर भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। भंडारे में दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आयोजन स्थल को भव्य फूलों की सजावट, दीपों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया, जिससे वातावरण और भी आध्यात्मिक बन गया। भंडारे के दौरान भक्तों के लिए स्वच्छता, व्यवस्था और सेवा का विशेष ध्यान रखा गया। ग्राम ओखला सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे। आयोजन समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की गई। इस भंडारे ने आपसी भाईचारे और सेवा भाव का सुंदर संदेश दिया। यह जानकारी संजय पालीवाल ने दी।

श्रीमद् भागवत कथा भूमि पूजन का आयोजन आज, धर्ममय वातावरण में हुआ शुभारंभ

इंदौर ● संवाददाता

देवास नाका प्रॉपर्टी एसोसिएशन के तत्वावधान में सिंगापुर टाउनशिप, पुलिस चौकी के सामने आयोजित होने जा रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के लिए आज विधिवत भूमि पूजन का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों एवं धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही।

भूमि पूजन का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर कथा स्थल को पवित्र किया गया। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण एवं श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पूजन कर कथा की मंगल कामना की गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने फूल-माला अर्पित कर कथा के सफल आयोजन हेतु प्रार्थना की।

आयोजकों ने जानकारी दी कि 22 फरवरी 2026, रविवार से कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। इसके पश्चात प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक वृंदावन पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज के श्रीमुख से संगीतमय कथा का रसपान कराया जाएगा, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में संयोजक श्री चिन्टू सिलावट,विक्की रघुवंशी,विक्की यादव, पप्पू जी शर्मा, गुड्डू जी जैसवाल, सहित निवेदक मंडल के सदस्य हरिओम मीणा,विशाल श्रीवास्तव, सुनील वाघमोडे, लक्की मौर्य, कमल वाड़े, ललित शर्मा एवं यशवंतसिंह पंवार उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर कथा आयोजन को भव्य एवं सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, संस्कार और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। आयोजकों ने समस्त क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें और धर्ममय वातावरण का हिस्सा बनें।

लिव-इन पार्टनर ने युवती की हत्या की : कॉलेज परिसर में किया हमला, दूसरे युवक से सबंध को लेकर हुआ था विवाद

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर के सुगनीदेवी कॉलेज परिसर में गंभीर हालत में मिली युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती को राहगीरों ने घायल अवस्था में एमवाय अस्पताल पहुंचाया था। उसके हाथों और शरीर पर कई टैटू बने हुए थे, वहीं शरीर पर ब्लेड से काटने के निशान भी पाए गए थे। शुरुआती जांच में डॉक्टरों को उसके साथ ज्यादती की आशंका हुई, जिसके चलते सैंपल भी लिए गए थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती पर हमला उसके लिव-इन पार्टनर ने किया था। आरोपी ने हत्या की नीयत से पत्थर से वार किया था। देर रात इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया।

खाली मैदान में किए थे वार

टीआई आरडी कानवा की टीम ने इस मामले में युवती के दोस्त मुकेश कोरी (45) (निवासी तीन पुलिया) को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक युवती और मुकेश कुछ समय से साथ रह रहे थे और दोनों नशे के आदी थे। शनिवार को दोनों

के बीच विवाद हुआ था। मुकेश युवती का खर्च उठाता था और उसे शक था कि युवती के अन्य युवकों से अवैध संबंध हैं। नशे की हालत में उसने खाली मैदान में युवती पर पत्थर से हमला किया और उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि युवती मूल रूप से इटारसी की रहने वाली थी और पिछले कुछ वर्षों से इंदौर में रह रही थी। उसके शरीर पर कई टैटू गुदे हुए थे। शुरुआत में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन युवती की मौत के बाद अब पुलिस धाराएं बढ़ाकर हत्या का केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

साथ में बैठकर पी थी शराब

मुकेश ने पुलिस को बताया कि बीते चार दिनों से युवती उसके साथ रह रही थी। शुक्रवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे दोनों ने परदेशीपुरा इलाके से अवैध शराब खरीदी और पी। इसके बाद वे एक ग्राउंड में बैठ गए। इसी दौरान युवती के अन्य लोगों से संबंधों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। नशे की हालत में मुकेश ने पत्थर उठाकर युवती के सिर और मुंह पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। सुबह करीब साढ़े छह बजे लोगों ने युवती को गंभीर हालत में पड़ा देखा और पुलिस एफआरवी को सूचना दी। पुलिस ने उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार रात उसकी मौत हो गई।

पुलिस चेकिंग देखकर भागा बाइक चोर, घेराबंदी कर पकड़ा

5 बाइकें जब्त, शौक के लिए करता था चोरी ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी भी गिरफ्तार

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर की हीरानगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को पकड़ा है। उसके पास से चोरी की पांच बाइकें बरामद हुई हैं। आरोपी शौक पूरा करने के लिए बाइकें चुराता था। उसके खिलाफ हीरानगर थाने में पहले भी चोरी का एक मामला दर्ज है।

टीआई सुशील पटेल के मुताबिक, पुलिस टीम ने मयंक उर्फ चिराग, पिता गोपाल अठोनिया, निवासी सेठी नगर, विजयनगर को पकड़ा है। आरोपी पुलिस की चेकिंग देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने पांच बाइकें चुराना कबूल किया है।

102 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया बदमाश

वहीं क्राइम ब्रांच ने 102 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चिंटू उर्फ चिट्टी, निवासी भागीरथपुरा को पकड़ा है। आरोपी लक्ष्मीबाई नगर के पास क्राइम ब्रांच को दिखाई दिया था। आरोपी चिंटू के खिलाफ पहले भी अन्य थानों में अपराध दर्ज हैं। वह ब्राउन शुगर की पुड़िया बनाकर बेचता था। क्राइम ब्रांच ने उसे रिमांड पर लिया है। वहीं एरोड्रम पुलिस ने भी सुमित पथरोड, निवासी पंचवटी नगर को 9 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

लसूडिया रिसोर्ट में शराबी युवकों ने सिंगर को पीटा

युवकों ने मंत्री के नाम से धमकाया भी, पुलिस मौके पर पहुंची

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर के लसूडिया इलाके में शनिवार रात एक रिसोर्ट में सिंगर निलेश पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब रिसोर्ट में सिंगिंग प्रोग्राम चल रहा था। गायक को पीटने के बाद, जब रिसोर्ट मैनेजर और स्टाफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो युवकों ने मंत्री के नाम का हवाला देकर धमकाया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवक कार लेकर चले गए। अभी सिंगर ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

लसूडिया बायपास पर स्थित द एस्केप वर्ल्ड रिसोर्ट में गायक निलेश प्रोग्राम कर रहे थे। इसी दौरान कुछ शराबी युवक गाना बंद करने के लिए कहने लगे। निलेश ने ध्यान न देने पर एक युवक ने माइक छीनकर थप्पड़ मार दिया। निलेश ने अपना बचाव किया और युवक को धक्का दिया, जिसके बाद उसके साथी भी विवाद के लिए खड़े हो गए। इस बीच, रिसोर्ट के मैनेजर और स्टाफ ने गायक का बचाव किया। शराबी युवकों ने उनसे भी बदतमीजी की। बाद में निलेश ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के सामने भी युवक रिसोर्ट स्टाफ से बदतमीजी कर रहे थे और बीजेपी के मंत्री के नाम से धमकियां दे रहे थे। रिसोर्ट के अनुसार, सभी शराबी युवक कार नंबर MP09AS4537 से आए थे, जिस पर लिखा था "बीजेपी सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डलावदा।" हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।

इंदौर में यूथ वॉक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड : नेहरू स्टेडियम से 3 किलोमीटर लंबी वॉक हुई, 10 हजार युवाओं ने लिया हिस्सा

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर में युवा नशा-उन्मूलन जागरूकता वॉक (यूथ वॉक–2026) ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) में अपना नाम दर्ज कराया है। 8 फरवरी 2026 को हुए इस आयोजन में लगभग 10 हजार युवाओं ने हिस्सा लिया, जिससे नशा विरोधी जन-जागरूकता के क्षेत्र में यह कार्यक्रम एक विश्व रिकॉर्ड बन गया।

3 किलोमीटर लंबी यह वॉक नेहरू स्टेडियम से सुबह 9 बजे शुरू हुई। कार्यक्रम के आयोजक रुद्राक्ष गोलू शुक्ला के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए उन्हें सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना और समाज में जनजागरण फैलाना है। आयोजकों का दावा है कि यूथ वॉक में 20 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए।

'नशे से दूर रहें युवा'

कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद

के प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव, बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। इस अवसर पर खगेंद्र भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी युवा है और इसी कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के युवाओं को नशे की लत में फंसाकर कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और यदि वे सही दिशा में आगे बढ़ें तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने रुद्राक्ष शुक्ला द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं।

25 हजार युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन

रुद्राक्ष गोलू शुक्ला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अब तक करीब 25 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रतिभागियों को आयोजन स्थल पर ही टी-शर्ट और कैप दी जाएगी। करीब 3 किलोमीटर लंबी यह वॉक नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर जीपीओ, छावनी, मधु मिलन, एमवाय और शिवाजी वाटिका होते हुए पुनः नेहरू स्टेडियम पहुंचेगी। इसमें कई स्कूल-कॉलेजों और एकेडमी के युवा शामिल होंगे।

इंदौर के खजराना में मिला नाबालिग का शव, कुएं से निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा

इंदौर। इंदौर के खजराना से लापता एक 14 वर्षीय नाबालिग समीर का शव रविवार दोपहर इलाके में ही मिला है। वह शनिवार शाम से लापता था। परिवार के लोगों ने रात में थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से परिजन और पुलिस उसकी तलाश कर रहे थे। खजराना पुलिस को सूचना मिली थी कि स्टार चौराहे के पास एक मैदान के नजदीक बने कुएं में एक शव पड़ा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया है। समीर के परिवार में उसका एक भाई है। उसके पिता की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार को समीर का इलाके में रहने वाले कुछ नाबालिगों से विवाद हुआ था। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

कलेक्टर की सख्ती बेअसर, शराब माफिया फिर सड़क पर

कार्रवाई के बाद भी ठेले, गुमटियां और अतिक्रमण बरकरार, हादसे का इंतज़ार क्यों? प्रशासन कब करेगा निर्णायक वार

खरगोन ● रविन्द्र परमार

शहर में अवैध शराब अहातों के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने डायवर्सन रोड से अवैध अहाते, गुमटियां और टपरियां हटाईं, लेकिन यह सख्ती महज़ कुछ घंटों की साबित हुई। कार्रवाई के दो दिन बाद ही शराब दुकान के बाहर फिर ठेले लग गए, सड़क जाम होने लगी और शराबियों की भीड़ लौट आई। कहार समाज के सामूहिक विवाह के दौरान सामने आई अव्यवस्था के बाद उठाया गया कदम आज खोखला नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यही है क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है, या अवैध शराब माफिया पर कभी निर्णायक वार होगा?

शहर में अवैध शराब अहातों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भले ही सुर्खियों में रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल रही है। डायवर्सन रोड पर शुक्रवार को एसडीओपी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने सड़क किनारे चल रहे अवैध शराब अहातों पर बुलडोज़र चलाया, टपरियां तोड़ीं और गुमटियों को आग के हवाले किया। दावा किया गया कि ये अहाते खुद शराब ठेकेदार द्वारा संचालित थे, जहां दिन-रात शराबियों का जमावड़ा लगाकर सड़क को जाम किया जा रहा था। कार्रवाई के पीछे वजह भी बेहद गंभीर थी। दो दिन पहले कहार समाज के सामूहिक विवाह समारोह के दौरान शराब दुकान के बाहर बेकाबू भीड़, अवैध गुमटियां और ठेलों ने पूरे रोड को जाम कर दिया था। उसी दौरान कलेक्टर और एसपी वहां से गुजरे और अपनी आंखों से अव्यवस्था देखी। कलेक्टर के सख्त निर्देश पर पुलिस हरकत में आई और अवैध अहातों को ध्वस्त किया गया। लेकिन यह सख्ती महज़ 48 घंटे भी असरदार साबित नहीं हो सकी, सवाल यह है कि क्या यह सख्ती सिर्फ दिखावे के लिए थी? क्योंकि आज फिर वही तस्वीर सामने है शराब दुकान के बाहर ठेले, अतिक्रमण और शराबियों की भीड़। सड़क फिर संकरी, यातायात फिर बाधित और हादसों का खतरा फिर मंडराने लगा है। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों का गुस्सा अब उबाल पर है। उनका साफ कहना है कि एक दिन की कार्रवाई से शराब माफिया नहीं रुकता। जब तक ठेकेदारों पर सीधी, कठोर और लगातार कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अवैध अहातों का यह खेल चलता रहेगा।

कांग्रेस को जी राम जी कहने में संकोच, इसलिए वीबी जी रामजी योजना को लेकर फैला रही भ्रम : मंत्री नागर चौहान

भाजपा के जिला स्तरीय सम्मेलन में वीबी जी राम जी योजना को जन-जन तक पहुंचाने का किया आह्वान

मंत्री नागर सहित खंडवा सांसद ने कहा. इतिहास में पहली बार मजदूरों के लिए 1.51 लाख करोड़ के बजट का किया प्रावधान

खरगोन ● संवाददाता

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) योजना के प्रचार- प्रचार को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रुप में प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राजपुत, पूर्व कृषि राज्यमंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, महेश्वर विधायक राजकुमार मेव ने जिला पदाधिकारियों, मंडल पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच योजना से किस तरह मजदूरों का हित एवं गांव का विकास होगाए इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्राह्मणे ने कहा कि वीबी जी रामजी योजना गांव, शहर के साथ ही किसान और मजदूर की दशा और दिशा बदलने वाली योजना है, क्योंकि इसमें मजदूर को रोजगार की शत. प्रतिशत गारंटी होगी। उन्होंने वीबी जी राम जी योजना के साथ ही हाल ही में प्रस्तुत बजट को जन-जन तक पहुंचाकर उसके लाभ जनता को बताने की अपील की है।

मुख्य अतिथि एवं वक्ता मंत्री श्री नागर ने पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नए बदलाव की सोच को लेकर वीबी जी रामजी योजना और बजट लागू कराया है। इन दोनों कार्यक्रमों का लाभ जन-जन को मिले, इसके लिए इसका प्रचार. प्रसार करना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे विपक्षी दल याने कांग्रेस इन योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैए लेकिन इनसे पहले हमें जनता को इनके फायदे बताने है। कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि मनरेगा बंद कर दी गई लेकिन मनरेगा बंद नही हुई है। उन्हें केवल जी राम जी कहने में संकोच है। इसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में काम के लिए 53.50 लाख करोड़ का बजट पारित किया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इसमें अकेले मजदूरों के लिए 1.51 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।

रामजी के नाम से विरोधियों के पेट में मरोड़

सांसद श्री पाटील ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वीबी जी रामजी योजना में भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर मजदूर, किसान और गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। योजना में बदलाव से मजूदर, किसान को कोई प्रभाव नही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के पेट में जी राम जी नाम देने से मरोड़ पड़ रही है। उन्हें हमेशा राम जी के नाम से चिढ़ रही है। यही कारण है कि वह योजना के नाम से जनता में भ्रम फैला रहे है। भाजपा कार्यकर्ताओंए पदाधिकारियों को चाहिए में वे गांव.गांव चौपाल लगाकर जनता को बताएं कि इससे गांव का विकास होगा। योजना में अब सारे निर्णय लेने के अधिकार ग्रामीणो और ग्राम सभा को दे दिए है। इसमें किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। रबी और खरीफ सीजन में जहां इस योजना में काम बंद रहेगा तो किसानों को मजदूर आसानी से मिलेंगेए वहीं मजदूरों को भी खेतों में रोजगार मिलेगा।

ग्राम विकास के लिए 87 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1.51 लाख करोड़ का प्रावधान

विधायक श्री पाटीदार ने कहा कि इस योजना का मूल लक्ष्य गांवों को सशक्त बनाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में जवाहर रोजगार जैसी योजनाएं चलायी गयी, लेकिन उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा। इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। मजदूरों के जॉब कार्ड का दुरुपयोग हुआ। इन सब को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने पूरी पारदर्शिता लाने के लिए इसमें बदलाव कर मजदूरों को गांव में ही रोजगार देने की महती योजना शुरु की है। इस योजना से गांव और मजदूर की दशा और दिशा बदले इसके लिए 87 हजार करोड़ के बजट को बढ़ाकर सीधे 1 लाख 51 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह योजना गांव के विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सीधे हितग्राही के खाते में राशि पहुंचेगी।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कांतिलाल कर्मा, व पूर्वी मंडल मीडिया प्रभारी रवि परमार ने बताया कि बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजपुत, वीबी जी रामजी योजना जिला संयोजक वीरेंद्र पाटीदार ने भी संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय बजट जिला संयोजक हरे सिंह चावड़ा, आजीवन सहयोग निधि संयोजक एवं जिला महामंत्री विवेक भटोरे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जगदीश पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष परसराम चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह डंडीर, वरिष्ठ नेता चंदर सिंह वास्कले आदि मंचासीन थे। बैठक का संचालन सतनाम कुशवाह ने किया एवं आभार जिला उपाध्यक्ष श्रीमती शालिनी रतोरिया ने माना।

यह रहे मौजूद

भाजपा जिला उपाध्यक्ष शंभू सिंह मनहर, जिला उपाध्यक्ष प्रभा राठौर, जिला मंत्री अनुराग दांगी, जिला मंत्री अमिता मंत्री, भीम सिंह जाधव, विजय पटेल, पूर्वी मंडल अध्यक्ष अभिलाष अत्रे, आकाश गुप्ता, सत्येन्द्र टोपी, रवि सोनी, प्रदीप वर्मा, अमित मौर्य, दिलीप जोशी, ताराचंद यादव, शीतल राठौर, वीणा जायसवाल, पुर्वा व्यास, बेबी मंडलोई पार्षद, पूजा वोरे, गीतांजलि तिवारी, माया खोड़े सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

संत नरहरि महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई

खरगोन ● संवाददाता

अहिर सुवर्णकार समाज द्वारा समाज के संत शिरोमणि श्री नरहरि महाराज की 440वीं पुण्यतिथि स्वर्णकार कॉलोनी स्थित समाज के भवन 'सोनारवाड़ा' में बड़ी धूमधाम से मनाई गई जिसमें मुख्य अतिथि खरगोन के विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार के साथ साथ नगर के गणमान्य नागरिक नरेंद्रसिंह चावला, सोनी समाज महिला अध्यक्ष मंजूला सोनी, ज्योतिषाचार्य बसंत सोनी, कीर्ति जैन, योगेश सोनी, दिलीप सोनी, बद्रीलाल सोनी, रमेश सोनी के साथ बड़ी संख्या में समाजजन और मातृशक्ति उपस्थित थी। कार्यक्रम में संत श्री के पूजन एवं दीपप्रज्वलन के उपरांत नरहरि महाराज की पालखी यात्रा निकाली गई और भंडारे का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने समाज की उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित किया और अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान में समाजजनों को संगठित रहते हुए अपनी युवा शक्ति विशेषतः नारी शक्ति को सतत प्रेरित करते रहना पड़ेगा तभी समाज का विकास संभव है। समाज के अध्यक्ष डॉ.शरद दिंडोरकर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि समाज के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबूलाल माड़ीवाले की स्मृति में बने इस सोनारवाड़ा भवन में विगत एक दशक से प्रतिवर्ष नरहरि महाराज की पुण्यतिथि ऐसे ही धूमधाम से मनाई जाती रही है। कार्यक्रम में नवनिर्मित महिला मंडल कार्यकारिणी की घोषणा भी हुई जिसमें महिला मंडल की अध्यक्षा मोनिका संजय दिंडोरकर के साथ अन्य पदों की नवनियुक्ति की गई। कार्यक्रम का संचालन मार्गदर्शिका हर्षाली अधिकार पंडित,भूषण डिंडोरकर एवं महिला मंडल सचिव अनुषा अधिकार ने किया। आभार डॉ.सुमित दिंडोरकर ने माना।

हनीट्रैप के मामले में पुलिस ने किया खुलासा

3 महिलाओं सहित 2 पुरुषों को किया गिरफ्तार

आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल

एक साल में करीब 40 लोगों को बनाया शिकार

एसडीओपी ने पत्रकारवार्ता में किया खुलासा

पहली बार फरियादी के आगे आने के बाद हुई कार्यवाही

सनावद ● संवाददाता

पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए लाखों की वसूली एवं ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह पर बड़ा एक्शन लेते हुए इसमें शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह में 3 महिलाओ सहित 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा पत्रकारवार्ता में किया। एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया कि 5 लोगों का गिरोह था। जिसमें गिरोह की महिला बुजुर्गों को बुला कर आपत्तिजनक वीडियो बनवाकर ब्लैकमेल करती थी। एक फरियादी के बयान के आधार पर महिलाएं वीडियो वायरल करने के साथ पुलिस में जाने की धमकी देकर फरियादी से की ढाई लाख की मांग कर रही थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को फरियादी से रुपए लेते गिरफ्तार किया। एसडीओपी रावत ने बताया कि यह कार्य एक साल से ज्यादा समय से चल रहा था। जिसमें करीब 40 लोगों को शिकार बनाया गया है। यह कार्यवाही टी आई धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।

आकाश गुप्ता एआईजे यूथ विंग के जिलाध्यक्ष मनोनीत

पत्रकार साथियों ने ओल्ड पीआरओ परिसर पर किया स्वागत, दी बधाई

खरगोन। भारतीय पत्रकार संघ (एआईजे) यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष धवन माहेश्वरी ने नगर के युवा पत्रकार आकाश गुप्ता को एआईजे यूथ विंग का खरगोन जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। उक्त नियुक्ति एआईजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन व यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जैन की सहमति से की गई है। श्री गुप्ता का नगर के पत्रकारों द्वारा ओल्ड पीआरओ परिसर में पुष्पहार पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। एआईजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीजुद्दीन शेख, प्रदेश संयोजक आमिर शेख, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम कुशवाह, जिलाध्यक्ष प्रकाश भावसार, संरक्षक आशुतोष पुरोहित, तहसील अध्यक्ष राजकुमार सोनी, वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा, मुकेश ठक्कर, नरेंद्र भटोरे, सदाशिव वर्मा, संजय पाराशर, अजय तिवारी, रामेश्वर बड़ोले, प्रवीण पाल, रवि परमार,संदीप ठक्कर, अनवर जिंद्रान, मनीष मडाहर, शुभम बगलाने, अबूबकर जिया, दिनेश सागौरे, दिलीप पंचोली, मोहन जोशी, पुरुषोत्तम सोनी, कांतिलाल कर्मा, सतीश गांगले, रईस खान, लुकमान खत्री, रफीक मंसूरी, जमीर मंसूरी, श्याम गुप्ता, सुरेश राठौर सहित अनेक पत्रकार साथियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए गुप्ता को बधाई दी है। गुप्ता ने महत्वपूर्ण दायित्व मिलने पर समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की रीति-नीति अनुसार राष्ट्र व पत्रकारिता के हित में कार्य करने की बात कही है।

अप्राकृतिक संबंध से इनकार करने पर नाबालिग ने की युवक की पत्थर मारकर हत्या

खरगोन ● संवाददाता

जिले की कसरावद पुलिस ने एक युवक के अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है। अप्राकृतिक संबंध से इनकार करने पर एक नाबालिग ने 42 वर्षीय युवक की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी नाबालिग ने

हत्या के बाद शव को निर्वस्त्र हालत में छोड़कर फरार हो गया था। चार दिन की गहन पूछताछ के बाद आरोपी नाबालिग ने अंधे कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया है। कसरावद थाना क्षेत्र के बेड़ी इलाके में 31 जनवरी को अंधे कत्ल होने से कसरावद में हडकंप मच गया था। एएसपी शकुंतला रूहल ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। एएसपी रूहल ने मीडिया को बताया की 31 जनवरी को राकेश चौहान का शव कसरावद के पुरातत्व संग्रहालय के पास बेड़ी क्षेत्र में मिला था। नाबालिग ने मृतक युवक पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। मना करने पर गुस्से में आरोपी नाबालिग ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया यह मामला अंधे कत्ल का प्रतीत हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर एफएसएल, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की। करीब चार दिन की गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को चिन्हित कर उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि मृतक उस पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इससे नाराज होकर उसने गुस्से में पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी और शव को मौके पर ही निर्वस्त्र हालत में छोड़कर फरार हो गया। एएसपी शकुंतला रूहल के अनुसार, आरोपी नाबालिग को विधि अनुसार अभिरक्षा में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की है।

11वीं की छात्रा से लव जिहाद केस में दूसरी गिरफ्तारी

आरोपी माज खान की कार में ओसाफ ने किया था रेप; मछली गैंग से भी नाता

भोपाल ● संवाददाता

भोपाल में एमडी तस्करी, लव जिहाद और जमीनें कब्जा करने वाले यासीन मछली गैंग का एक और अपराध सामने आया है। मछली गैंग के गिरफ्तार सदस्य मोनिस खान के छोटे भाई माज खान को रविवार को पुलिस ने खानूगांव लव जिहाद मामले में गिरफ्तार किया है।

दरअसल, 2 जनवरी को कोहेफिजा पुलिस ने 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। पीड़िता ने खानूगांव इलाके में कार में रेप करने, धर्म बदलने का दबाव बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 जनवरी को मुख्य आरोपी ओसाफ अली खान (19) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब रविवार को दूसरे आरोपी माज खान की गिरफ्तारी हुई है। वारदात में इस्तेमाल काले कांच की थार माज की ही थी। पूरा घटनाक्रम उसकी जानकारी में था। बता दें कि माज का बड़ा भाई मोनिस एमडी तस्करी मामले में जमानत पर है। माज खुद को एक प्रतिष्ठित जिम का संचालक बताता है। फिलहाल, कोर्ट ने उसे 13 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस माज के सीडीआर डिटेल सहित मोबाइल में मौजूद डाटा का परीक्षण भी कराएगी।

माज का मददगार हेड कॉन्स्टेबल सस्पेंड

वहीं, डीसीपी जोन-3 अभिनव चौकसे ने माज को पेश कराने और बिना रिमांड लिए जेल भिजवाने की डील के आरोप में कोहेफिजा थाने के हेड कॉन्स्टेबल ज्ञानेंद्र दिवेदी को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि ज्ञानेंद्र ने पूरी डील एक आलीशान होटल में की थी। ज्ञानेंद्र के संदिग्ध आचरण के चलते टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ला ने 7 फरवरी को उसके खिलाफ प्रतिवेदन डीसीपी को सौंपा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। रेप और लव जिहाद का आरोपी ओसाफ 12वीं क्लास का छात्र है। उसके पिता

डॉक्टर जबकि मां सरकारी स्कूल में टीचर हैं। कोहेफिजा थाना टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ला के अनुसार, ओसाफ अक्सर छात्रा की सहेली से मिलने स्कूल के आसपास आता था। इसी सहेली के माध्यम से उसकी पहचान पीड़िता से हुई। पिछले साल जुलाई में आरोपी ने पीड़िता को भोपाल घुमाने के बहाने बुलाया और खानूगांव के सुनसान इलाके में ले गया। वहां कार के अंदर आरोपी ने छात्रा के साथ रेप किया। विरोध करने पर उसने शादी का झांसा देकर उसे चुप करा दिया।

वीडियो दिखाकर एक लाख रुपए की डिमांड की

ओसाफ ने पीड़िता को पता चले बिना रेप के दौरान उसका वीडियो बना लिया था। कुछ समय बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से 1 लाख रुपए की मांग की। बदनामी के डर से छात्रा ने किसी तरह 40 हजार रुपए का इंतजाम कर आरोपी को दिए।

नंबर ब्लॉक करने पर दोस्तों को दिखाया वीडियो

40 हजार रुपए लेने के बाद भी ओसाफ की ब्लैकमेलिंग जारी रही। वह बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। तंग आकर छात्रा ने उसे सोशल मीडिया और फोन पर ब्लॉक कर दिया, तो ओसाफ ने अलग-अलग फोन नंबरों से कॉल कर परेशान किया। जब छात्रा नहीं मानी, तो ओसाफ ने निजी वीडियो छात्रा के दोस्तों को दिखा दिया। इसके बाद छात्रा ने अपने मौसेरे भाई और हिंदू संगठन के लोगों की मदद से थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, जबरन दुआएं पढ़वाईं

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि ओसाफ उस पर धर्म बदलने का दबाव डालता था। उससे कई बार जबरन धार्मिक दुआएं भी पढ़वाई गईं। पुलिस ने ओसाफ अली खान का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है।

यूजीसी के फैसलों के विरोध में करणी सेना का मशाल-जुलूस

भोपाल में पुलिस ने राजभवन जाने से रोका; बोले- यूजीसी का काला कानून वापस लो

भोपाल ● संवाददाता

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) से जुड़े हालिया फैसलों के विरोध में रविवार शाम भोपाल में क्षत्रिय करणी सेना ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस भारत माता चौराहा से शुरू होकर राजभवन तक जाना था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उसे रोक लिया। राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए सिर्फ पांच लोगों को जाने की अनुमति दी। ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के निर्णयों को लेकर समाज की आपत्तियां दर्ज कराई गईं।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने कहा कि यूजीसी काला कानून वापस लिया जाए। क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष और भोपाल जिला अध्यक्ष आशु सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा और प्रदेश महिला अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने की। उन्होंने कहा कि जुलूस में भोपाल सहित आसपास के जिलों से सैकड़ों करणी सैनिक शामिल हुए। इसके अलावा सवर्ण समाज के कई संगठन और आम नागरिक भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। फैसले छात्र हितों और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने वाला आशु सिंह के अनुसार, यूजीसी से जुड़े कुछ हालिया निर्णयों को लेकर समाज में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि ये फैसले छात्र हितों और सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इसी असंतोष को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से शासन तक पहुंचाने के लिए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। करणी सेना का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा।

जन परिषद ने किया अजातशत्रु जी का अभिनंदन

भोपाल ● संवाददाता

जन परिषद के उपाध्यक्ष एवं पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आदरणीय श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव के मुख्यमंत्री के ओएसडी बनने पर जन परिषद की कोर कमेटी के कुछ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदाधिकारियों में सर्वश्री रामजी श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, दुर्गेश रायकवार, मोहन अग्रवाल एवं सुनील श्रीवास्तव उपस्थित थे। सर्व श्री एन के त्रिपाठी, अजय श्रीवास्तव नीलू एवं महेंद्र जोशी के भोपाल से बाहर होने के कारण उन्होंने फोन पर बधाईयां दी। श्री अजातशत्रु ने चर्चा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि मेरे सभी मित्रों एवं शुभचिंतकों की है। उन्होंने कहा कि जन परिषद के सामाजिक एवं रचनामक उद्देश्यों को मूर्तरूप देने के लिए, उनसे जो भी बन पड़ेगा, वे उसके लिए कृत संकल्प हैं।

भोपाल कॉन्फ्रेंस में CJI की मौजूदगी में न्यायिक रोडमैप तय

7 साल तक की सजा वाले मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर, मीडिया ट्रायल पर भी चर्चा

भोपाल ● संवाददाता

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, 25 राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित कर न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण पर जोर दिया है। भोपाल में हुए न्यायाधीशों के सम्मेलन में सात साल तक की सजा वाले अपराधों के मुकदमों को प्राथमिकता देकर लंबित मामलों से निपटने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार किया गया है। इसके साथ ही मीडिया ट्रायल और राज्यों की बार-बार मुकदमेबाजी कम करने पर भी कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी इंडिया द्वारा भोपाल में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिए आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का केंद्र बिंदु एकीकृत, कुशल और जन-केंद्रित न्यायपालिका का निर्माण था। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में हुए इस सम्मेलन में प्रशासन के संस्थागतकरण और एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति के निर्माण पर डिस्कशन किया गया। इसका उद्देश्य न्यायिक शासन को पारंपरिक मॉडल से एक रणनीतिक, डेटा-आधारित प्रणाली में परिवर्तित करना है लेकिन यह ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय आधुनिक कानूनी मांगों की जटिलताओं से निपटने में सक्षम हों और साथ ही देश भर में संस्थागत अखंडता बनाए रखें। अकादमी के निदेशक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर मामलों का निराकरण किया जाएगा, इसके लिए रोडमैप तैयार किया गया है। 7 साल तक की सजा वाले अपराधों के मुकदमों को प्राथमिकता देकर लंबित मामलों से निपटने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार किया गया है। मीडिया ट्रायल के मुद्दों पर चर्चा हुई और इस बात पर जोर दिया गया कि निर्दोषता की धारणा को संरक्षित करने के लिए न्याय न्यायालय में ही मिलना चाहिए।

भोपाल मेट्रो से शहर को देख झूम उठे बच्चे : 400 बच्चों ने सफर किया; स्टॉफ से पूछा- मेट्रो कैसे दौड़ती है?

भोपाल ● संवाददाता

भोपाल मेट्रो में रविवार को करीब 400 बच्चों ने सफर किया। मेट्रो के अंदर से शहर को देख वे झूम उठे। इस दौरान उन्होंने स्टॉफ से सवाल भी पूछा कि मेट्रो दौड़ती कैसे है?

केंद्रीय स्कूल नंबर-1 के बच्चों ने केंद्रीय स्कूल मेट्रो स्टेशन से एम्स तक करीब 6 किलोमीटर तक सफर किया। इस दौरान उन्होंने रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, डीबी मॉल और एम्स हॉस्पिटल देखा। साथ ही ऊंचाई से डॉ. अंबेडकर (जीजी फ्लाईओवर) ब्रिज, होशंगाबाद का वीर सावरकर सेतु भी देखा। साथ पहुंचे मेट्रो और

स्कूल स्टॉफ से जिज्ञासावस कई सवाल भी पूछे। बच्चों को टिकट में मिली छूट नई पीढ़ी को मेट्रो से रूबरू कराने के मकसद से बच्चों को यह सफर करवाया गया। इस दौरान उन्हें टिकट में छूट भी दी गई। बच्चों ने प्लेटफॉर्म, ट्रेन का संचालन, यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम के बारे में भी जानकारी ली। क्या ले जाने की मनाही, हर जानकारी दी भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक हजारों यात्री सफर कर चुके हैं, लेकिन पहली बार इतनी अधिक संख्या में स्कूली बच्चों को मेट्रो में सफर करवाया गया। इसके चलते उन्हें मेट्रो से जुड़ी हर जानकारी दी गई। ये भी बताया कि वे मेट्रो में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं।

भोपाल में 100 मीटर के दायरे में मंदिर-शराब दुकान

आयोग सदस्य बोले- भगवान से ही उनके होने का प्रमाण मांगा; ये जवाब हास्यास्पद

भोपाल ● संवाददाता

भोपाल की अरेरा कॉलोनी में 100 मीटर के दायरे में ही शराब दुकान और मंदिर है। पिछले 1 साल से रहवासी इसका विरोध जता रहे हैं। रविवार को मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो यहां पहुंचे और जिला प्रशासन के उस जवाब की पड़ताल की, जो आयोग को दिया गया है। सदस्य कानूनगो मंदिर के पास शराब दुकान देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी भगवान से ही उनके होने का प्रमाण मांग रहे हैं, ये जवाब हास्यास्पद है।

10 नंबर मार्केट के पास अरेरा कॉलोनी में आर्य समाज मंदिर के सामने पहुंचे आयोग सदस्य कानूनगो ने रहवासियों से बात भी की। सदस्य कानूनगो ने बताया कि अरेरा कॉलोनी में मंदिर के सामने ही शराब की दुकान संचालित होने का मामला सामने आया है। यह विषय इसलिए भी गंभीर है कि यहां पर भगवान से भगवान के स्वयं होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। इस संबंध में आयोग ने जिला प्रशासन को नोटिस दिया था। जो जवाब मिला, उसके बारे में भोपाल के लोगों को पता होना चाहिए। ये मिला

जवाब कानूनगो ने बताया, जवाब में कहा गया कि शराब की दुकान से 100 मीटर के दायरे में कोई गजट नोटिसफाइड धर्म स्थल नहीं है। यह जवाब हास्यास्पद है। सरकार का नियम और मंशा है कि धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी तक कोई शराब दुकान संचालित नहीं होगी। शराब दुकान और धर्म स्थल का आपस में मेल नहीं हो सकता है। जिला प्रशासन के जवाब में भगवान नोटिसफाइड नहीं है। आज मैं सिर्फ यही देखने आया हूं कि वे कौन लोग हैं, जो भगवान से सरकारी नोटिफिकेशन में भगवान से अस्तित्व का प्रमाण मांग रहे हैं।

आबकारी अधिकारी पर नाराजगी जताई कानूनगो ने कहा कि जिला आबकारी अधिकारी को भी दो दिन पहले सूचित किया था, लेकिन वे यहां नहीं आए। इस पर कानूनगो ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई लोग ने तख्तियां लेकर विरोध जताया आयोग सदस्य कानूनगो के पहुंचने की खबर मिलने पर कई रहवासी इकट्ठा हो गए। हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने शराब दुकान हटाने की मांग की। निरीक्षण के बाद आयोग सदस्य ने स्थानीय आबकारी अधिकारियों से बात की। इस दौरान विभाग की ओर से कहा गया कि ठेकेदार को नोटिस देकर दुकान अगले कुछ दिन में हटा ली जाएगी। पहले शिकायत कर चुके रहवासी अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी ने बताया, अरेरा कॉलोनी में जिस जगह पर शराब दुकान संचालित हो रही है, वह पूरी तरह से आवासीय उपयोग के लिए है, लेकिन वर्तमान में इसका कमर्शियल तरीके से उपयोग हो रहा है, जो पूरी तरह मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर निगम अधिनियम 1956 का उल्लंघन है। अवैध अहाता भी चल रहा उन्होंने बताया, उक्त शराब की दुकान पूरी तरह आवासीय परिसर में, आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से संचालित की जा रही है। रहवासियों की शिकायत के बाद नगर निगम भोपाल ने 19 नवंबर 2025 को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद शराब की दुकान बेखौफ और अवैध रूप से संचालित होती रही वहीं तिरपाल से ढंक कर अवैध अहाता संचालित होता पाया जोकि कानून अपराध हैं ।

40 मीटर दूर ही है आर्य समाज मंदिर रहवासी त्रिपाठी ने बताया, पिछले करीब एक साल से स्थानीय लोग जिला प्रशासन, नगर निगम, आबकारी विभाग और मानव अधिकार आयोग तक शिकायतें दर्ज कर चुके हैं। जिला प्रशासन ने तो बेहद चौंकाने वाली बात कही है। अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में शराब दुकान के 40 मीटर की दूरी पर स्थित आर्य समाज मंदिर को मंदिर मानने से ही इनकार कर दिया।

दुकान की वजह से परेशान रहवासी शराब दुकान के कारण क्षेत्र की शांति, सामाजिक वातावरण और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रतिदिन वहां पर भीड़, वाहनों की आवाजाही, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और शोर-शराबे की स्थिति बनी रहती है। जिससे महिलाओं और बच्चों के लिए आवागमन तक कठिन हो गया है।

त्रिपाठी ने कहा कि आवासीय भूखंड पर शराब दुकान चलाना न केवल अवैध है, बल्कि यह भोपाल नगर निगम के मानचित्र और भूमि उपयोग नीति के भी पूरी तरह विपरीत है।

यह मांग उठा चुके रहवासी

- भूखंड E-4/21 पर संचालित शराब दुकान को तत्काल बंद किया जाए।
- संबंधित शराब दुकान संचालक एवं अनुमोदन देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

भोपाल में तीन दिन डिजिटल अरेस्ट रहा मजदूर : साइबर ठगों ने टेरर फंडिंग का आरोप लगाकर डेढ़ लाख रुपए ठगे

भोपाल। भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक मजदूर को तीन दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। ठगों ने उससे डेढ़ लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। हालांकि, शिकायत मिलते ही पुलिस ने संबंधित खातों को होल्ड कराया और पीड़ित को ठगों के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस के मुताबिक 45 वर्षीय राजकुमार छोला इलाके में रहता है और मजदूरी करता है। तीन दिन पहले उसके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एनआईए का अधिकारी बताया और कहा कि उसके खाते से एक आतंकी को फंडिंग की गई है। इससे पीड़ित घबरा गया। इसके बाद आरोपियों ने तस्दीक के नाम पर उसे वीडियो कॉल पर आने को कहा। वीडियो कॉल पर आते ही बदमाशों ने पुलिस लिखी स्कॉर्पियो दिखाई।

नंबर बंद करने पर एन्काउंटर की धमकी दी

नंबर बंद करने या फरार होने की कोशिश करने पर एन्काउंटर की धमकी दी गई। इससे घबराए फरियादी ने उनके सवालों के जवाब देना शुरु किए और स्वयं को निर्दोष बताया। इसके बाद आरोपियों ने कहा कि वह भला आदमी लगता है और उसे मामले से बाहर निकाल देंगे, लेकिन डिजिटल निगरानी में रहना होगा। पीड़ित ने इसके लिए हामी भर दी। इसके बाद आरोपी शुक्रवार से रविवार सुबह तक उसे निगरानी में रखे रहे।

सेटलमेंट कराने के नाम पर ठगी रकम

अलग-अलग ठग अधिकारी बनकर उससे पूछताछ करते रहे। इसी दौरान केस में सेटलमेंट कराने के नाम पर कई किस्तों में करीब डेढ़ लाख रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। रविवार को परिजन ने मामले की जानकारी थाने में दी। इसके बाद छोला मंदिर पुलिस ने पीड़ित को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया।

संपादकीय

मुफ्त उपहारों की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की नजर

देश में चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को रिझाने के लिए जिस तरह मुफ्त तोहफों या उपहारों की राजनीति की जा रही है, उसने एक तरह से नतीजों की शुचिता को कसौटी पर रख दिया है। भारतीय राजनीति में पिछले कई वर्षों से यह प्रवृत्ति जटिल होती गई है। हालांकि इस मसले पर सवाल भी उठे हैं और मुफ्त तोहफों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने को लोकतंत्र के लिए एक घातक चलन बताया गया है।

देश में चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को रिझाने के लिए जिस तरह मुफ्त तोहफों या उपहारों की राजनीति की जा रही है, उसने एक तरह से नतीजों की शुचिता को कसौटी पर रख दिया है। भारतीय राजनीति में पिछले कई वर्षों से यह प्रवृत्ति जटिल होती गई है। हालांकि इस मसले पर सवाल भी उठे हैं और मुफ्त तोहफों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने को लोकतंत्र के लिए एक घातक चलन बताया गया है। विडंबना यह है कि लगभग सभी राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वे भी इसी तरीके को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर जो दल या गठबंधन सत्ता में होते हैं, वे वादों या घोषणाओं के साथ-साथ चुनावों के ठीक पहले कोई योजना या कार्यक्रम लागू करने के जरिए भी मतदाताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुफ्त उपहारों को भारतीय राजनीति में एक घातक प्रवृत्ति बताया है, लेकिन इस पर रोक को लेकर अब तक कोई ठोस नियमन सामने नहीं आ सका है। यही वजह है कि आज राजनीतिक दलों के बीच एक तरह की होड़ देखी जाती है कि वोट हासिल करने के लिए मतदाताओं को कौन कितना ज्यादा लाभ पहुंचाने की घोषणा करता है। नतीजतन, स्वच्छ चुनाव और विवादरहित नतीजे आज एक सदिच्छा की तरह लगने लगे हैं। राजनीतिक दलों से यह उम्मीद करना मुश्किल हो गया लगता है कि इस दिशा में वे अपनी ओर से कोई ऐसी पहल करेंगे, जो चुनावी जीत के लिए मुफ्त की रेवड़ियों के चलन पर रोक लगाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मसले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है, तो इससे एक बार फिर मुफ्त की चुनावी रेवड़ियों पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि करीब चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने केंद्र और निर्वाचन आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें चुनाव से पहले 'अतार्किक मुफ्त उपहार की घोषणा' या इसे वितरित करने वाली राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त या उसका पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। उस समय पीठ ने इसे गंभीर मुद्दा करार दिया था और कहा था कि कभी-कभी मुफ्त उपहार योजना का बजट नियमित बजट से अधिक हो जाता है। सवाल है कि अगर कोई मतदाता मुफ्त की सौगात दिए जाने के असर में किसी उम्मीदवार को वोट देता है, तो क्या यह एक तरह की सौदेबाजी नहीं कही जाएगी? अगर कोई सत्ताधारी पार्टी चुनावों के ठीक पहले किसी योजना या कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाती है, तो उसकी जीत को कितना निष्पक्ष माना जाएगा? दिनोंदिन बढ़ती मुफ्त उपहारों की राजनीति के बीच होने वाले चुनाव को किस हद तक स्वच्छ और स्वतंत्र कहा जाएगा?

चीनी मांझा.... पतंग का शौक या मौत का जाल?

किसी खास किस्म के मांझे से दूसरों की पतंग काटने की लोगों के भीतर कैसी भूख है कि यह राह चलते निर्दोष लोगों और मासूम पक्षियों के लिए जानलेवा बन जाती है। यह जानते-समझते हुए भी लोग खतरनाक मांझे से पतंग उड़ाते हैं, जिनसे उलझ कर हर साल कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब ऐसे हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे से होने वाली मौत को हत्या की श्रेणी में रखते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, एक दिन पहले ही लखनऊ में मांझे वाले धागे से गला कटने की वजह से एक युवक की मौत हो गई थी। राज्य सरकार अब विशेष अभियान चला कर चीनी मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई करेगी। सवाल है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद ये धागे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चोरी-छिपे या खुलेआम कैसे बिक रहे हैं। ये कहां से आते हैं और इनके स्रोत क्या हैं? यह किसकी लापरवाही का नतीजा है और इसे रोकने में संबंधित एजंसियां अब तक नाकाम क्यों रही हैं? यह दुखद है कि जन सरोकार के इतने बड़े मसले की हर स्तर पर उपेक्षा होती रही है। समय-समय पर चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने की बातें की गईं, लेकिन वे कारगर साबित नहीं हुईं। प्रश्न यह है कि इन धागों को बेचने की छूट कौन देता है? गौरतलब है कि इसे खरीदने और बेचने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा पंद्रह के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मगर इनका सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता। चीनी मांझे पर कई राज्यों में रोक है। दिल्ली में भी पाबंदी है, लेकिन यहां भी ये बेरोकटोक बिकते हैं। साफ है कि चीनी मांझे के बाजार में पहुंचने से लेकर बिकने तक, कहीं भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। खतरनाक मांझे के साथ पतंग उड़ाने का ऐसा क्या जुनून है लोगों में कि जोखिम की आशंका के बावजूद वे न सजा से डरते हैं, न जुर्माने से। इस तरह के जानलेवा धागे से पतंग उड़ाने की जिद को किस तरह देखा जाएगा?

माहवारी को मिला गरिमा का अधिकार

विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं।

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता।

विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है। न्यायालय ने शिक्षा को एक 'मल्टीप्लायर राइट' बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके।माहवारी स्वच्छता केवल पैड उपलब्ध कराने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ जुड़ा है स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्णकृसही जानकारी। आज भी अनेक लड़कियाँ पहली माहवारी के समय भय, भ्रम और अपराधबोध से घिर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से कोई वैज्ञानिक और संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में यदि स्वास्थ्य शिक्षा को गंभीरता से लागू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह डर और संकोच स्वत: समाप्त हो सकता है। यह भी सच है कि माहवारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी पुरुषों की भूमिका को भी प्रश्नों के घेरे में लाती है। जब तक पुरुष-चाहे वे पिता हों, शिक्षक हों, प्रशासक हों या नीति-निर्माता, इस विषय को केवल महिलाओं का मामला मानकर किनारे करते रहेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने समाज और खासकर पुरुषों को संवेदनशील बनने का अवसर दिया है। जागरूकता का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि पुरुषों को सहृदय और जिम्मेदार बनाना भी है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी से जुड़ी चुनौतियाँ और भी गंभीर हैं। वहाँ आज भी कपड़े, राख या अस्वच्छ साधनों का उपयोग आम है, जिससे संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सरकारी योजनाएँ और गैर-सरकारी प्रयास मौजूद हैं, परंतु उनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यदि ईमानदारी से लागू होता है, तो यह नीति और जमीन के बीच की खाई को पाटने में सहायक हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि माहवारी स्वच्छता को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर महिला अधिकारों के व्यापक ढाँचे में देखा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार-तीनों इस विषय से सीधे जुड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लड़की केवल इसलिए स्कूल न जा सके क्योंकि उसके पास सेनेटरी पैड नहीं हैं, वह व्यवस्था संविधान की आत्मा के विपरीत है। इसलिए यह फैसला सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूती देता है। आज भारत नए प्रवेश के साथ आगे बढ़ने की बात करता है-डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है। **किंतु यदि इस विकास की गाथा में महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताएँ और सम्मान शामिल नहीं हैं, तो यह प्रगति खोखली सिद्ध होगी। वास्तविक विकास वही है जो सबसे कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का साहस रखे। माहवारी जैसे विषय पर खुली चर्चा उसी साहस का प्रतीक है। समाज में जन-जागृति लाना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कानून और आदेश दिशा दिखा सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनाते हैं। यदि हम सचमुच एक समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय भारत का निर्माण चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ नया भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को विकास के केंद्र में रखना ही होगा। माहवारी से मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक सुविधा नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान होती है।**

हिमालय संकट और सत्ता की बेरुखी

कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में भी बर्फबारी लगभग न के बराबर हुई है। इस वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है।

देश के राजनीतिक दल देश के लोगों के लिए कितने गैरजिम्मेदार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में शोध पर आधारित दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी के बारे में किसी ने चिंता तक जाहिर नहीं की। इन रिपोर्टों में सर्दी के मौसम में हिमालय क्षेत्र जंगलों में लगने वाली आग के कारण और भूस्खलन के नए केंद्रों की जानकारी दी गई है। दरअसल ऐसी जानकारियों को गंभीरता से लेने पर राजनीतिक दलों के वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। यही वजह है अत्यंत संवेदनशील और आम जन—जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में जगह नहीं पाते हैं।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1,756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। यह संख्या महाराष्ट्र (1,028), कर्नाटक (924), मध्य प्रदेश (868) और छत्तीसगढ़ (862) जैसे उन राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से जंगल में आग के मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। आमतौर पर दिसंबर जंगल में आग के लिहाज से सबसे शांत महीना माना जाता है, लेकिन पिछले तीन सालों में उत्तराखंड के लिए यह धारणा गलत साबित हुई है। दिसंबर में उत्तराखंड में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जंगल की जमीन में नमी का लेवल बहुत कम है। उत्तराखंड की तरह, हिमाचल में भी पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह से कोई बारिश नहीं हुई थी। इसी तरह, कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में भी बर्फबारी लगभग न के बराबर हुई है। इस वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। देहरादून में तो कई बार यह इंडेक्स 300 के पार जा चुका है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की ओर से कराए गए एक अध्ययन ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि पर्यावरण प्रदूषण में फॉरेस्ट फायर की भूमिका 15 से 20 प्रतिशत तक है, जो कि बेहद गंभीर आंकड़ा है। उत्तराखंड का हिमालयी भूगोल, जलवायु परिवर्तन और तेज विकास की दौड़ मिलकर राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में राज्य में तेज गति से सड़क निर्माण और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इसका परिणाम यह निकला कि चारधाम यात्रा रूट के आसपास लगभग 100 नए भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए। पहले से मौजूद संवेदनशील जोन भी और अधिक खतरनाक हो गए हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन तेजी से निर्माण कार्यों ने पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया है। सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की गई, भारी मशीनरी का उपयोग हुआ, जंगलों का व्यापक कटान किया गया। इन सभी वजहों से पुराने भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हुए और नए भूस्खलन क्षेत्र भी बन गए। उत्तराखंड के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर करीब 400 भूस्खलन स्थल चिन्हित किए गए हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। साल 2025 के मानसून सीजन में अब तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हुई है। उत्तराखंड में 2016 से 25 तक प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। पिछले 11 वर्षों में 27,197 प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें अतिवृष्टि और भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख हैं। साल 2025 में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुईं, जिसमें 720 लोगों की मौत और 1207 लोग घायल हुए थे। इन 11 सालों के आंकड़े में केदारनाथ की साल 2013 में 16 और 17 जून को आई प्राकृतिक आपदा के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। उस दौरान अकेले केदारनाथ में ही 4400 से ज्यादा लोग या तो लापता हो गए थे या फिर मारे गए थे। हिंदुकुश हिमालय का इलाका भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी 11 बड़ी नदियां बहती हैं। वसंत के महीने में बर्फ पिघलने से ही इन नदियों को पानी मिलता है। लगभग 17 प्रतिशत आबादी पीने के पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। इसी पानी का उपयोग सिंचाई और हाइड्रोपावर के लिए भी किया जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के तापमान में वैश्विक औसत से 0.74एष्ट अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साल 2003 से 2020 तक हिमालय के अधिकांश हिस्सों में बर्फ से घिरे इलाकों में गिरावट देखी गई। पहले यहां औसतन 102 दिनों तक बर्फ रहती थी। अब हर दस साल में पांच दिन कम हो रहे हैं। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभों के कमजोर होने से पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में न के बराबर बर्फ गिरी। गढ़वाल में इस साल जनवरी में बर्फबारी का अभाव देखा गया। ऐसा पिछले 40 सालों में पहली बार हुआ है। कम हिमपात के चलते जटामांसी और कुटकी जैसी महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ीबूटियां विलुप्त हो रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में स्नो ड्रॉट या 'बर्फ का सूखा% जैसी स्थिति बन रही है। विशेष रूप से 3,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह प्रभाव सबसे अधिक देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में बेलगाम विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल एक दिन नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाबतलब किया। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल में भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं मानव निर्मित हैं। बिना वैज्ञानिक अध्ययन के फोर लेन रोड बन रहे हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उनके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। सिर्फ राजस्व कमाना सब कुछ नहीं।

चाहत ने हसरतें सीजन 3 में निभाया चुनौतीपूर्ण किरदार

हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज हसरतें सीजन 3 के नए एपिसोड नया किराएदार में चाहत पांडे ने स्मिता नाम की गृहिणी की भूमिका निभाई है। उनका किरदार कई मायनों में महिलाओं की जटिल भावनाओं, उनकी इच्छाओं और उनके संघर्ष को बयां करता है। स्मिता एक ऐसी महिला है, जो अपने पति के अचानक गायब होने के बाद अकेली और भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करती है। उसे अपनी दबंग सास के साथ रहना पड़ता है, जिससे उसके जीवन में दबाव और भी बढ़ जाता है। समाज की निगाहें, ऑफिस में हो रहे उत्पीडऩ और अपनी अधूरी इच्छाओं को दबाने की मजबूरी ने उसकी जिंदगी को थमा दिया है। लेकिन कहानी में बदलाव तब आता है, जब उसके घर में समर्थ नाम का एक युवा म्यूजिशियन किरायेदार बनकर आता है। उनकी बढ़ती दोस्ती स्मिता के भीतर छिपी हुई भावनाओं को फिर से जागृत करती है।

जैसे-जैसे स्मिता समर्थ के करीब जाने लगती है, अचानक उसके पति की वापसी हो जाती है। स्मिता को अब यह तय करना होता है कि वह समाज की बनाई गई मर्यादाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बंधी रहे या अपनी खुशी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुने। यह कहानी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि कभी-कभी जीवन में अपनी खुशी चुनना गुनाह नहीं, बल्कि जीवित रहने का तरीका है। चाहत पांडे ने अपने किरदार को लेकर कहा, स्मिता मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार है। स्मिता ऐसी महिला है, जिसे बचपन से सिखाया गया कि उसे अपने दर्द और अधूरी इच्छाओं को कभी व्यक्त नहीं करना है।

पति के गायब होने के बाद समाज उसे और भी सख्ती से नियंत्रित करने लगता है। इस किरदार के जरिए मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि जब एक महिला अपनी आवाज सुनती है, तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। चाहत ने आगे कहा, स्मिता की कहानी उसके अधिकारों को वापस पाने और यह स्वीकार करने की कहानी है कि अपनी खुशी चुनना कोई अपराध नहीं है। यह किरदार महिलाओं की भावनाओं, उनके संघर्ष और उनकी स्वतंत्रता की कहानी को बड़े ही संवेदनशील तरीके से पेश करता है। हसरतें सीजन 3 में चाहत पांडे का यह कदम ओटीटी की दुनिया में उनकी नई पहचान बनाने का भी अवसर है।

कुछ लोग मुझे एक्टिंग छोडऩे के लिए कर रहे मजबूर : पायल राजपूत

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की उभरती अभिनेत्री पायल राजपूत का कहना है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उन्हें एक्टिंग छोडऩे के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं हैं। पायल राजपूत ने एक बार फिर अपने संघर्ष, दृढ़ता और मजबूत इरादों को खुलकर रखा है। पायल का कहना है कि कठिन समय ने भले ही उन्हें हिलाया हो, लेकिन तोड़ा नहीं। पायल ने एक्स पर लिखते हुए कहा, 'वे चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं। कई बार मैं खुद से सवाल करती हूं कि क्या मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं पिछले 12 सालों की अपनी कड़ी मेहनत को याद करती हूं। तब मैं खुद से कहती हूं नहीं, मैं फेल हो सकती हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगी। उनका यह बयान उन सभी कलाकारों के दिल से जुड़ता है, जो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं।

नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म जैसे मुद्दों पर पायल पहले भी बेबाक रुख अपनाती रही हैं। उन्होंने अपने पिछले पोस्ट में लिखा था कि एक्टर बनना सबसे कठिन करियर में से एक है, क्योंकि यहां हर दिन अनिश्चितता से भरा होता है। उनके अनुसार अक्सर टैलेंट के ऊपर बड़े सरनेम, मजबूत कनेक्शन और पावरफुल एजेंट्स हावी हो जाते हैं। इस वजह से कई बार वे सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि उनकी मेहनत इस सिस्टम में पहचानी जाएगी भी या नहीं। उन्होंने कहा था कि अवसर अक्सर उन्हीं लोगों के पास चला जाता है जिनके पास प्रभावशाली पहचान या बैकग्राउंड होता है। इसके बावजूद पायल ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और उम्मीद बनाए रखी। उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ अपने टैलेंट और लगन पर भरोसा करती हैं और यही उन्हें आगे बढऩे की शक्ति देता है।

इस बीच पायल के पास कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं। वह मशहूर निर्देशक मुनि की तेलुगू फिल्म 'वेंकटलक्ष्मी में नजर आएंगी, जिसे तेलुगू, तमिल और हिंदी—तीनों भाषाओं में रिलीज करने की योजना है। इसके अलावा वह तमिल के बड़े बजट की एक अनटाइटल्ड फिल्म में भी काम कर रही हैं, जिसका निर्देशन आर.एस. दुरई सेंथिलकुमार कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग का पहला फेज चेन्नई में पूरा हो चुका है और यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक रोमांचक एक्शन-ड्रामा बताया जा रहा है। फिल्म में संगीत जिब्रान का है, सिनेमैटोग्राफी एस. वेंकटेश कर रहे हैं, जबकि एडिटिंग प्रदीप और आर्ट डायरेक्शन दुरईराज संभाल रहे हैं।

कलाकारों का पूरा दिन निकल जाता है काम में : अर्जुन बिजलानी

आठ घंटे की शिफ्ट को लेकर छोटे पर्दे के जाने-माने अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने खुलकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि टीवी इंडस्ट्री में काम करना कितना कठिन होता है। एक्टर ने टीवी इंडस्ट्री के लंबे वर्किंग आवर्स को बेहद मुश्किल बताया। उन्होंने कहा, कागज पर भले ही 12 घंटे की शिफ्ट लिखी जाती हो, लेकिन असल में कलाकारों का पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। शूटिंग के अलावा सेट तक आने-जाने का समय, मेकअप, और कई बार ओवरटाइम भी इसमें जुड़ जाता है, जिससे काम के घंटे और बढ़ जाते हैं। अर्जुन ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर किसी कलाकार की शूटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होती है, तो उसे सुबह 7 बजे उठना पड़ता है। 8 बजे तक घर से निकलना जरूरी होता है ताकि समय पर सेट पहुंचा जा सके। खासकर महिला कलाकारों को कई बार और भी जल्दी बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें मेकअप और तैयार होने में ज्यादा समय लगता है। इस वजह से उनका दिन और भी लंबा हो जाता है। उन्होंने कहा, शूटिंग अक्सर रात 9 बजे तक चलती है और कई बार इससे भी देर हो जाती है। शूट खत्म होने के बाद भी कलाकारों को मेकअप उतारने और कपड़े बदलने में समय लगता है। इसके बाद ट्रैफिक में घर लौटना एक अलग चुनौती होती है। कई बार कलाकार रात के काफी देर से घर पहुंचते हैं, जब शरीर पूरी तरह थक चुका होता है। अर्जुन बिजलानी ने कहा, सबसे मुश्किल बात यह है कि अगले दिन फिर वही दिनचर्या दोहरानी पड़ती है। शरीर को पूरा आराम मिलने से पहले ही फिर से काम पर निकलना पड़ता है। लगातार ऐसा होने से मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ती जाती है, जिसका असर कलाकारों की सेहत पर भी पड़ता है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अर्जुन ने बताया, एक समय ऐसा भी था जब तय समय से कहीं ज्यादा काम करना पड़ता था। कभी-कभी ऐसा महसूस होता था जैसे 30 दिनों के महीने में 35 दिन काम किया हो। यह दौर मेरे लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहद थकाने वाला था। लेकिन पहले के मुकाबले अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। पहले शूटिंग 14, 15, और 18 घंटे तक चलती थी। अब ज्यादातर प्रोड्यूसर्स कोशिश करते हैं कि शूट तय 12 घंटे में ही खत्म कर दिया जाए। जब उनसे पूछा कि क्या टीवी इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, तो अर्जुन बिजलानी ने कहा, तकनीकी रूप से यह संभव नहीं है। जब कोई शो हफ्ते में सातों दिन टेलीकास्ट होता है, तो इतने कम समय में काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

अर्जुन ने कहा, अगर काम के घंटे घटाकर 8 कर दिए जाएं, तो शो की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। दर्शकों तक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पहुंचाने के लिए कलाकारों और पूरी टीम को 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। काम और सेहत के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। बता दें कि टीवी की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार और रंगीन दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही दबाव से भरी होती है। दर्शक रोज अपने पसंदीदा कलाकारों को टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन उनकी मेहनत, थकान और मानसिक तनाव से अनजान रहते हैं।

बॉलीवुड में बदलाव पर जीनत अमान ने उठाए सवाल

हाल ही में इंस्टाग्राम पर भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने 1970 के दशक की फिल्म तीसरी आंख का एक खास सीन पोस्ट किया, जिसमें उनका किरदार बरखा काफी आक्रामक है और वह शरारती अंदाज में धर्मेंद्र के किरदार अशोक भोला का पीछा करती दिखती है। अभिनेत्री ने पोस्ट कर लिखा, पुरानी फिल्मों में सीन दोबारा देखना हमेशा एक अनोखा और मजेदार अनुभव होता है। कभी पता नहीं चलता है कि कौन सा सीन दिल को छू लेगा या फिर सोचने पर मजबूर कर देगा। अभिनेत्री ने आगे बताया कि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले फिल्म दोस्ताना का एक क्लिप शेयर किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार इंस्पेक्टर विजय किसी महिला को छेड़ता और स्लट-शेमिंग करता नजर आता है। अब तीसरी आंख का सीन शेयर कर उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ दो सालों में हिंदी सिनेमा में हीरोइनों की भूमिका इतनी तेजी से बदल गई? जीनत ने लिखा, फिल्म दोस्ताना में पुरुष किरदार आक्रामक था, जबकि तीसरी आंख में महिला का किरदार बरखा आक्रामक है और पुरुष का किरदार अनिच्छुक शिकार बनता है। यह एक तरह का जेंडर फ्लिप है। दोस्ताना का सीन गुस्सा दिलाता है, जबकि यह सीन मजेदार लगता है, क्योंकि पारंपरिक भूमिकाएं उलट गई हैं। अभिनेत्री ने बाद में ये साफ किया कि वह बरखा के इस व्यवहार का समर्थन नहीं करती, ठीक वैसे ही जैसे दोस्ताना में इंस्पेक्टर विजय के व्यवहार का समर्थन नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा, बॉलीवुड ने कई बार मस्ती और शरारत के नाम पर जुनून और दीवानगी को बढ़ावा दिया। उन्होंने असल प्यार दिखाने की बजाय जुनूनी रोमांस को महिमामंडित किया गया। मैंने भी इस तरह के रोमांस के विचार को फैलाने में भूमिका निभाई है। अब मैं इसे ठीक करने की छोटी कोशिश कर रही हूं।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, रिश्ते में सहमति होनी बेहद जरूरी है और सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। मैंने यह बात बड़ी मुश्किल तरीके से सीखी है। इस सीन पर आपकी टिप्पणियों का बेसब्री से इंतजार है। मुझे इसे पाकर बहुत खुशी हुई, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें मेरे प्यारे को-स्टार धर्मजी हैं, जिनके साथ मेरी सिर्फ प्यारी यादें हैं। बता दें कि जीनत अमान अक्सर अपनी पुरानी फिल्मों के सीन्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं और फैंस से हिंदी सिनेमा में आए बदलावों पर बात करती हैं।

जब पत्नी ने एक्टर को घर से निकाला, बोली- बाहर जाओ, पैसे कमाओ

अभिनेता आर माधवन आजकल हर दूसरी-तीसरी फिल्म में नजर आ रहे हैं। उनकी पिछले छह महीनों में करीब तीन फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से एक फिल्म धुरंधर है, जो अभी भी बॉक्स ऑफिस और ओटीटी दोनों पर धमाल मचा रही है। इसमें उन्होंने अजय सान्याल का रोल निभाया है, जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के किरदार से प्रेरित था। फिल्म धुरंधर में माधवन का रोल काफी कम था, लेकिन इसके पार्ट-2 में उनका रोल बड़ा और अहम होने वाला है।

फिल्म धुरंधर में सान्याल का किरदार निभाने वाले माधवन ने सुनाया किस्सा

बता दें माधवन इस समय हिंदी और साउथ दोनों फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिवली काम कर रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो चार साल तक एक्टिंग से दूर रहे। कोविड-19 से पहले माधवन काम से दूर थे, लेकिन इसी दौरान वह अपने अगले फेज की तैयारी में भी जुटे थे। हाल ही में उन्होंने उस दौर को याद किया, जब वह काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी सरिता ने उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया। रिपोर्ट के मुताबिक माधवन ने एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए बताया कि मेरी बीवी कहती है कि आप कभी काम से बाहर नहीं निकल सकते। आप तो तमिल कॉमेडी करते हैं, तमिल एक्शन करते हैं। ओटीटी करते हैं, हिंदी एक्शन करते हैं, इंग्लिश ओटीटी करते हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप घर पर बैठे हैं। कोरोना के समय 2020 में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बोलीं कि जाओ बाहर, कुछ काम करो, पैसे कमाओ।

माधवन ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने उनमें काम के प्रति आ रहे बदलाव पर ध्यान दिलाया। माधवन ने कहा कि एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या हो गया है? आप काम पर ऐसे जा रहे हो जैसे जल्दी से वापस आना चाहते हो। ये बात उनकी बहुत सही थी। माधवन धुरंधर-2 के बाद और भी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। कोविड के बाद से एक्टर का एक अलग ही रूप देखने मिला है, जो फिल्मी लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग भी है।

नेपाल को हराने में फूल गई इंग्लैंड की सांसे, रोमांचक मुकाबले में चार रन से दर्ज की जीता

मुंबई ● एजेंसी

नेपाल टी-20 विश्वकप का सबसे बड़ा उलटफेर करने के करीब पहुंच गया लेकिन इंग्लैंड ने अंतिम ओवर में धैर्य बनाये रखते हुए टी-20 विश्वकप के पांचवें मुकाबले में रविवार को चार रन से रोमांचक जीत हासिल की। इंग्लैंड ने सात विकेट पर 184 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। नेपाल ने लक्ष्य का जबर्दस्त ढंग से पीछा किया लेकिन अंत में छह विकेट पर 180 रन ही बना सका। सैम करन ने बेहतरीन आखिरी ओवर डाला और नेपाल को सिर्फ पांच रन ही बनाने दिये। जबकि 19वें ओवर में नेपाल ने 14 रन बनाये थे। जेकब बेथेल (55) और कप्तान हैरी ब्रूक (53) रनों की अर्धशतकीय शानदार पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 184 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया था। 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल ने 42 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा दिये।

आसिफ शेख (सात) और कुशल भुर्तेल (29) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद कप्तान रोहित पॉडेल और दीपेंद्र सिंह ऐरी की जोड़ी ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिये 82 रन जोड़े। 15वें ओवर में सैम करन ने दीपेंद्र सिंह ऐरी को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 29 गेंदों में छह चौके और एक छक्का लगाते हुए 44 रन बनाये। अगले ही ओवर में लियाम डॉसन ने रोहित पॉडेल को आउट कर पवेलियन भेज दिया। रोहित पॉडेल ने 34 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए 39 रन बनाये। आरिफ शेख 10 रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये लोकेश बम ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए जीत की उम्मीद जगा दी। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर ल्यूक वुड ने गुलशन झा (एक) को बोल्ड कर अपनी टीम को कुछ राहत दी।

नेपाल की टीम को मैच की आखिरी गेंद पर जीत के लिए छक्के की जरूरत थी लेकिन करन ने सिर्फ एक रन दिया। लोकेश बम 20 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद 39 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के विल जैक्स (नाबाद 39 और एक विकेट) को हरफनमौला प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार दिया गया। इंग्लैंड के लिए लियाम डॉसन ने दो विकेट लिये। जोफ्रा आर्चर, सैम करन, विल जैक्स और ल्यूक वुड ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 184 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जेकब बेथेल ने 35 गेंदों में चार चौके और चार छक्के लगाते हुए (55) और कप्तान हैरी ब्रूक ने 32 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के लगाते हुए (53) रनों की अर्धशतकीय पारियां खेली। वहीं विल जैक्स ने 18 गेंदों में एक चौके और चार छक्के उड़ाते हुए (नाबाद 39) रन बनाये। जॉस बटलर ने 17 गेंदों में 26 रन बनाये। इंग्लैंड के पांच बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह ऐरी और नंदन यादव ने दो-दो विकेट लिये। शेर मल्ला और संदीप लैमिछाने ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

न्यूज ब्रीफ

सूर्यकुमार ने अमेरिक के खिलाफ मैच में सफलता का श्रेय गंभीर को दिया

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम को अंडर-19 विश्वकप के पहले ही मुकाबले में कप्तानी पारी खेलकर जीत दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव ने इसका श्रेय कोच गौतम गंभीर की एक सलाह को दिया है। सूर्या ने कहा कि एक समय जब आधी टीम 77 रनों पर पेवेलियन लौट गयी थी तब उनपर काफी अधिक दबाव था पर बेक्र के दौरान कोच कोच ने उनसे अंत तक टिके रहने को कहा था। कोच का मानना था कि अगर वह अंत तक खेलेंगे तो रन बन जाएंगे। सूर्यकुमार ने इस मैच में 49 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्के लगाकर नाबाद 84 रन बनाए। इससे भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाकर 29 रन से जीत हासिल की। सूर्यकुमार ने बताया कि गंभीर ने उनसे कहा था कि वह अंत तक तक बल्लेबाजी करें क्योंकि वह जमने के बाद बड़े शॉट लगा सकते हैं। सूर्यकुमार ने कहा, मुझे बल्लेबाज के समय अंदाजा हो गय था कि इस विकेट पर 140 रन ही काफी हैं। मुझे इस प्रकार के विकेटों पर खेलने आ अनुभव है। इसलिए मेरा मानना था कि मैं यहां बड़ी पारी खेल सकता हूं। सूर्यकुमार छठे ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे और शुरुआत में उन्होंने धीमी बल्लेबाजी करते हुए केवल 7 रन बनाये। बाद में उन्होंने तेजी से खेलते हुए कमी पूरी कर दी। सूर्यकुमार ने 36 गेंदों में ही अर्धशतक लगा दिया। अंतिम ओवर में उन्हों चौके, छक्के लगाकर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया।

फहीम अशरफ बने अ20 विश्व कप 2026 के पहले प्लेयर ऑफ द मैच

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को तीन विकेट से हराकर टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की। यह जीत हालांकि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं थी। 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने शुरुआत अच्छी की और दस ओवर में दो विकेट पर 90 रन बना लिए थे, लेकिन मध्यक्रम के लगातार विफल होने से मैच बेहद रोमांचक हो गया। 16.1 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर सात विकेट पर 114 रन था और उसे जीत के लिए 34 रन चाहिए थे। मैदान पर संकट की इस घड़ी में फहीम अशरफ ने एक बार फिर साबित किया कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। 11 गेंदों पर नाबाद 29 रन की उनकी आतिशी पारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। 19वें ओवर में लोगान वान बीक की गेंद पर उन्होंने तीन लंबे छक्के और एक चौका लगाकर 24 रन बटोरे, जिससे मैच पूरी तरह पाकिस्तान की ओर झुक गया। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर मारा गया फहीम का चौका पाकिस्तान को तीन गेंद शेष रहते जीत दिला गया। उनकी इसी दमदार पारी के लिए उन्हें टी20 विश्व कप 2026 का पहला प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फहीम को 19वें ओवर में बड़ा जीवनदान भी मिला, जब ओडाउड ने उनका कैच तब छोड़ा जब वे केवल सात रन पर थे। यह गलती नीदरलैंड को मैच गंवाने की सबसे बड़ी वजह साबित हुई। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने 31 गेंद पर 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि सईम अयूब ने 13 गेंद में 24 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम इस मैच में प्रभाव छोड ` में नाकाम रहे और 18 गेंद पर केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए।नीदरलैंड की ओर से पॉल वान मीकेरेन ने शानदार गेंदबाजी की और फरहान व उस्मान खान को एक ही ओवर में आउट किया। अगली ही ओवर में बाबर का विकेट गिरा और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती गईं।

विराट, रोहित पर कोच गंभीर के दबाव बनानें की बातें गलत : सैकिया

मुंबई ● एजेंसी

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के मुख्य कोच गौतम गंभीर से कोई मतभेद नहीं हैं। साथ ही कहा कि ये दोनो ही उस स्तर के खिलाड़ी हैं जिन्हें कोई भी दबाव बनाकर बाहर नहीं कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड ने एक प्रकार से कोच गौतम गंभीर के रोहित शर्मा और विराट कोहली से मतभेदों की खबरों को खारिज कर दिया है। सैकिया ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही है कि गंभीर इन दोनो को बाहर होने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो सही नहीं है। इससे पहले कई लोगों का आरोप था कि टी20 विश्वकप 2024 जीतने के बाद रोहित और विराट ने इस प्रारुप से संन्यास ले लिया था। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट को भी छोड़ दिया। अब दोनों केवल एकदिवसीय ही खेलते हैं और इसमें भी उनपर दबाव बनाया जा रहा है। सैकिया ने कहा कि लोगों की अपनी धारणा हो सकती है पर गंभीर क्या कोई भी विराट और रोहित जैसे खिलाडियों पर दबाव नहीं बना सकता है। उन्होंने कहा, 'ऐसी धारणा हो सकती है पर विराट हमेशा टीम में हैं। गंभीर भी टीम में हैं। हम परिणाम देखते हैं और कुछ नहीं । ' साथ ही कहा कि विराट पर टेस्ट से संन्यास लेने के लिए दबाव नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी को कोई भी किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उनके जैसे खिलाड़ी को कोई भी बदलने या कोई फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वह भारतीय क्रिकेट के सितारे हैं। जब तक वह स्वयं चाहें, कोई भी उन्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बोर्ड किसी भी खिलाड़ी के करियर में हस्तपेक्ष नहीं करता है। विराट और रोहित के टेस्ट से संन्यास के बाद उनके एकदिवसीय करियर को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थीं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई सीरीज के बाद दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास से लेंगे पर ऐसा नहीं हुआ। दोनो ने ही काफी अच्छा खेल दिखाकर अपने आलोचकों को शांत करा दिया. साथ ही कहा कि लोग क्या कहते हैं उसपर हम न तो जवाब दे सकते हैं न ही कुछ कर सकते हैं। सैकिया ने कहा कि दोनों के बीच सब कुछ सामान्य है और कोई लड़ाई नहीं हो रही है। सैकिया ने कहा. 'मैंने कभी उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा। दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। ,

अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना विश्व कप जीतने से भी बड़ा सपना : राशिद खान

नई दिल्ली ● एजेंसी

अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान भले ही दुनिया भर में क्रिकेट खेलकर कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हों, लेकिन अपने देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उनका सपना आज भी अधूरा है। युद्ध और अस्थिरता से प्रभावित अफगानिस्तान में अब तक एक भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आयोजित नहीं हो सका है। हालात इतने चुनौतीपूर्ण रहे कि टीम को अपने घरेलू मैच विदेशों में खेलने पड़ते हैं। भारत के ग्रेटर नोएडा, देहरादून और लखनऊ से लेकर यूएई के शारजाह और अबूधाबी तक, कई शहर लंबे समय तक अफगानिस्तान टीम के 'घरेलू मैदान बने रहे। इसके बावजूद राशिद अपने इस सपने को छोडऩे को तैयार नहीं हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 मैच से पहले राशिद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह हमारे लिए विश्व कप से भी बड़ा सपना है। अगर हम अफगानिस्तान में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेल पाते हैं, तो दुनिया देखेगी कि वहां लोग खिलाडिय़ों का कितना सम्मान करते हैं और क्रिकेट का कितना आनंद लेते हैं। अपने देश में खेलना किसी सपने से बढ़कर है। राशिद ने बताया कि दुनिया के हर कोने में, खासकर आईपीएल के दौरान, उन्हें अपार प्यार मिलता है, लेकिन घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का अनुभव अद्वितीय होगा। उन्होंने कहा, 'भारत में आईपीएल या अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए हमें हमेशा लगा कि लोग अपने सितारों को कितना प्यार देते हैं। हमें भी ढेर सारा स्नेह मिला है, खासकर 2023 विश्व कप में। लेकिन अफगानिस्तान में खेलना एक अलग एहसास देगा। तब दुनिया हमारे देश की खूबसूरती भी देखेगी। राशिद को उम्मीद है कि एक दिन ऐसा माहौल जरूर बनेगा, जब कोई अंतरराष्ट्रीय टीम अफगानिस्तान में सीरीज खेलने पहुंचेगी।

राशिद ने अफगानिस्तान की घरेलू क्रिकेट संरचना की कमजोरियों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि देश में छोटे प्रारूप के पर्याप्त मैच न होने की वजह से सीमित ओवरों की टीम चुनना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा, 'अगर बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी की तरह प्रतिस्पर्धा हो जाए, तो हम नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। असली प्रतिभा घरेलू क्रिकेट से ही निकलती है। अंत में, राशिद ने अफगानिस्तान महिला क्रिकेट टीम को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते देखने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि किसी भी मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात होती है।

आखिरी ओवर में मिली जीत पर फहीम अशरफ का बड़ा बयान, कहा - हम ऐसे हालात के आदी हैं

नई दिल्ली ● एजेंसी

पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के अपने शुरुआती मुकाबले में नीदरलैंड को आखिरी ओवर में हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के नायक बने हरफनमौला खिलाड़ी फहीम अशरफ, जिन्होंने 11 गेंदों में नाबाद 29 रन जड़कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। खासतौर पर 19वें ओवर में फहीम द्वारा लगाए गए तीन छक्कों और एक चौके ने मैच की दिशा ही बदल दी। उस ओवर में कुल 24 रन आए जिसने पाकिस्तान की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। मैच के बाद पुरस्कार समारोह में फहीम ने कहा कि वे ऐसी परिस्थितियों के आदी हो चुके हैं। उन्होंने बताया, 'हम पिछले एक साल से इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। दिल की धड़कन ऊपर-नीचे होती रहती है, लेकिन हमें भरोसा रहता है कि एक ओवर में जितने भी रन चाहिए हों, बना सकते हैं। फहीम ने यह भी बताया कि वह और शाहीन शाह अफरीदी विकेट बचाकर अंत तक खेलने की रणनीति पर टिके थे। दोनों ने आठवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण 34 रनों की नाबाद साझेदारी की। 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान एक समय मजबूत स्थिति में था, जब 10 ओवर में टीम ने दो विकेट पर 90 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद विकेटों का लगातार गिरना शुरू हुआ और 16.1 ओवर तक स्कोर सात विकेट पर 114 रन हो गया। टीम को आखिरी दो ओवर में 29 रन चाहिए थे, जिसे फहीम ने अपनी विस्फोटक बैटिंग से आसान बना दिया। कप्तान सलमान आगा ने स्वीकार किया कि टीम ने यह मैच कठिन तरीके से जीता। उन्होंने कहा, 'हमें यह मैच मुश्किल तरीके से जीतना पड़ा, लेकिन फहीम को पूरा श्रेय जाता है। हमें पता था कि विपक्षी टीम दबाव बनाएगी। वहीं नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि उनकी टीम ने जज्बे के साथ खेला, लेकिन अहम मौकों पर चूक गई। उनके अनुसार, यदि टीम 160 के आसपास का स्कोर बनाती, तो नतीजा अलग हो सकता था। यह जीत पाकिस्तान के अभियान की शानदार शुरुआत मानी जा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि मैच की परिस्थितियाँ कठिन थीं और फहीम ने दबाव में परिपक्वता दिखाते हुए टीम को जीत दिलाई।

बॉटम

'फोर्स मेज्योर प्रावधान के तहत नहीं खेलने के कारण बताने कहा

आईसीसी ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार पर अड़े पीसीबी को फटकार लगायी

दुबई ● एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने टी20 विश्वकप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बहिष्कार की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीसी) की घोष्णा पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती हे। आईसीसी ने पीसीबी से पूछा है कि उसने 'फोर्स मेज्योर प्रावधान के तहत मैच के बहिष्कार करने का जो फैसला लिया है वह किन आधारों पर लिया है, ये उसे बताना होगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने कहा थ कि पाकिस्तान सरकार के निर्देशों के कारण वह मैच नहीं खेल सकती। वहीं आईसीसी ने अभी तक इस मामले में उम्मीद नहीं छोड़ी है। दोनो के बीच अभी बातचीत जारी है जिससे इस मामले का हल निकल सकता है। आईसीसी भी इस मामले को बातचीत से सुलझान चाहती है। पाक बोर्ड जिस फोर्स मेज्योर प्रावधान के तरत मैच नहीं खेलने की बात कर रहा। वह अब अमल में आता है जब अप्रत्याशित हालात होते है। तब वह सरकार के आदेश का हवाला देकर फोर्स मेज्योर प्रावधान के तहत खेलने से मना कर सकता है। आईसीसी के के मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (एमपीए) के अनुसार, यदि कोई बोर्ड फोर्स मेज्योर क्लाज का हवाला देता है, तो उसे यह भी साबित करना होता है कि उसने स्थिति को संभालने के लिए क्या प्रयास किए। आईसीससी ने पाक बोर्ड से ये भी पूछा है किउसने मैच आयोजित करने के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक उपाय अपनाए, साथ ही सबूत भी मांगे हैं। आईसीसी ने पीसीबी को चेताय है कि यदि यह मैच नहीं होता है, तो इससे खेल, को व्यवसाहिक और गवर्नेंस स्तर पर गंभीर नुकसान हो सकता है। हालांकि आईसीसी ने साफ किया है कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन उसके संविधान के तहत गंभीर उल्लंघन की स्थिति में किसी सदस्य को निलंबित या बाहर करने का अधिकार उसके पास है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत-पाक मैच के बहिष्कार की घोषणा करते हुए कहा कि वह ये फैसला बांग्लादेश बोर्ड के समर्थन के लिए किया है। इससे पहले आईसीसी ने भारत में खेलने से इंकार करने के लिए । बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। पीसीबी का मानना है कि उसका कानूनी पक्ष मजबूत है। उसने साल 2014 के विवाद को उदाहरण के तौर पर पेश किया है, जिसमें भारत सरकार की अनुमति न मिलने के कारण द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो पाई थी। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी निदेशक इमरान ख्वाजा और मुबाशिर उस्मानी पीसीबी अधिकारियों के साथ बातचीत कर मामले का हल दिकालने का प्रयास कर रहे हैं।

न्यूज ब्रीफ

प्रधानमंत्री मोदी का कुआलालंपुर में भव्य औपचारिक स्वागत, दोनों देशों के बीच मित्रता हुई गहरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा ने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने और रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर पुत्रजया स्थित पेरदाना पुत्र में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यह सम्मान न केवल कूटनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा था, बल्कि भारत और मलेशिया के बीच गहरे होते भरोसे और स्थायी मित्रता का भी प्रतीक बना। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा भारत और मलेशिया के बीच सभ्यतागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चाएं हुईं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि भारत-मलेशिया की साझेदारी साझा आकांक्षाओं और आपसी विश्वास पर टिकी है, जिसे इस यात्रा के माध्यम से एक नई ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस यात्रा के महत्व को साझा करते हुए कहा कि भारत और मलेशिया विश्वास और दोस्ती पर आधारित अपनी साझेदारी को और गहरा कर रहे हैं। उनके दो दिवसीय दौरे में उच्च-स्तरीय बैठकें, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल रहे। इस यात्रा का एक विशेष पहलू सांस्कृतिक जुड़ाव रहा, जहाँ प्रधानमंत्री ने मलेशिया में भारतीय विरासत, विशेषकर तमिल समुदाय द्वारा अपनी परंपराओं को संरक्षित रखने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान तिरुमुराई भक्ति गीतों के गायन को बेहद सराहनीय बताया। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच का व्यक्तिगत तालमेल और सौहार्द तब स्पष्ट रुप से दिखाई दिया, जब प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को एक साथ कार में यात्रा करते देखा गया। कुआलालंपुर में एक सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साथ जाना दोनों नेताओं के बीच की गहरी समझ और व्यक्तिगत केमिस्ट्री को दर्शाता है।

लंदन में बैठे भगोड़े हीरा कारोबारी मामा-भांजे को ब्रिटेन की अदालतों ने दिया झटका

नई दिल्ली। लंदन में बैठे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी, दोनों के लिए बुरी खबर है। अलग-अलग मामलों में ब्रिटेन की अदालतों ने साफ संकेत दे दिया कि अब देरी, बहाने और साजिश के आरोप काम नहीं आएंगे। लंदन हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के बकाया ऋण मामले में नीरव मोदी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने दृष्टिहीनता, अवसाद और जेल की परेशानियों का हवाला देकर ट्रायल टालने की मांग की थी। नीरव इस समय एचएमपी पेंटनविले जेल में बंद है और वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में पेश हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट जज ने साफ कहा कि नीरव को ट्रायल में 'समान अवसरÓ मिलेगा और उसे किसी तरह की 'महत्वपूर्ण क्षतिÓ नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह याचिका देरी करने के पैटर्न का हिस्सा लगती है। मतलब साफ बीमारी और हालात का सहारा लेकर समय खींचने की कोशिश अब कोर्ट को मंजूर नहीं। नीरव पर भारत में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गवाहों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप हैं। 2019 से वह ब्रिटेन की जेल में है और प्रत्यर्पण रोकने की उसकी कई अपीलें पहले ही खारिज हो चुकी हैं। वहीं नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी को भी लंदन से करारा झटका लगा है। ब्रिटिश कोर्ट ने भारत सरकार और अन्य के खिलाफ उसके 'अपहरणÓ वाले मुकदमे में सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट का आदेश दे दिया यानी चोकसी को करीब 6 लाख पाउंड की रकम कोर्ट में जमा करनी होगी, ताकि अगर वह केस हार जाए तो विपक्ष के खर्च वसूल हो सकें। कोर्ट ने साफ कहा कि चोकसी के दावों में 'उच्च संभावनाÓ नहीं दिखती।

संजय राउत ने समझौते को राष्ट्रद्रोह करार दिया

भारत : अमेरिका ट्रेड डील, पीएम मोदी ने कारोबारी दोस्त को बचाने देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया

मुंबई ● एजेंसी

शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत के बयान ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर राजनैतिक गलियारे में नई हलचल मचा दी है। उन्होंने समझौते को सीधे तौर पर राष्ट्रद्रोह करार देकर भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान पर हमला बताया है।

15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए नियति से समझौते का जिक्र उद्धव गुट के नेता राऊत ने कहा कि जिस संकल्प के साथ भारत ने आजादी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संकल्प को तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका के साथ हुआ व्यापार समझौता भारत को फिर गुलामी की दिशा में धकेल रहा है। खासकर किसानों और लोगों के भविष्य के साथ समझौता किया। उद्धव गुट के सांसद राऊत के बयान के बाद यह मुद्दा केवल व्यापार नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद, संप्रभुता और आजादी के मूल्यों से जुड़ी बड़ी राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ चार माह से अटके व्यापार समझौते को जल्दबाजी और हड़बड़ी में पूरा किया गया और भारत के साथ समझौता होने की घोषणा सबसे पहले अमेरिका ने बड़ी खुशी से की। इसके पहले पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही पहले 'सीजफायर का ऐलान किया था। अब व्यापार समझौते के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ट्रंप और अमेरिकी कृषि मंत्री ने बताया कि इस समझौते से उनके देश को वैसे लाभ हुआ। क्या प्रधानमंत्री मोदी भी बता सकते हैं कि यह समझौता उनके लिए लाभकारी है। साथ ही कहा कि ट्रेड डील से भारत पर टैरिफ 50 से 18 प्रतिशत

हो गया है। इस जीत बताया गया जो कि सरासर गलत है। अब तक अमेरिका भारत पर औसतन 3 फीसद से कम टैरिफ लगाता रहा है। अब अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट पर 18 फीसदी टैरिफ लगाएगा। भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर 'शून्य टैरिफ लगाएगा। अब तक भारत अमेरिकी सामानों पर 30 से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता था। यह अब भारत के लिए घाटे का सौदा है। भारत अब से अमेरिका से ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद और कोयले सहित अन्य वस्तुओं की 5 अरब डॉलर की खरीद बढ़ाएगा। राउत ने कहा कि भारत अब रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। नए समझौते के अनुसार भारत को अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा। ऐसा करने से भारत को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से केवल गुजरात के हीरा व्यापारियों को ही लाभ दिखा है। मुंबई का हीरा व्यापार गुजरात में स्थानांतरित हो गया। यह वहीं बना रहे इसलिए भारत से निर्यात किए जाने वाले कच्चे हीरे और रंगीन रत्नों पर अमेरिका में शून्य प्रतिशत यानी जीरो कर होगा। वहीं 18 प्रतिशत कर के बोझ से श्रमिक, किसान और छोटे व्यापारी मारे जाएंगे। अमेरिकी किसानों के उत्पाद, अनाज, दालें, दूध, पनीर, फल, फूल, सब कुछ भारतीय बाजार में 'शून्य करों के कारण बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। इससे भारतीय किसानों का बचा-खुचा अस्तित्व खत्म होगा। सांसद राउत ने कहा कि अमेरिका के साथ हुआ समझौता देश को गिरवी रखने जैसा सौदा है। इस समझौते के लिए मोदी ने किसकी अनुमति ली चार माह पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कुछ शर्तें लगा दी थी। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। तब मोदी ने कहा था कि तेल किससे खरीदना है यह भारत खुद तय करेगा। अब मोदी ने ट्रंप की शर्त मान ली है। मोदी सरकार का यह रुख कि वह अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं करने देगी, अब धराशायी हो गया है। जब अमेरिकी 'माल पूरे भारतीय बाजार में आएगा, तब 'मेक इन इंडिया और हमारी देसी कंपनियों का क्या होगा। उद्धव गुट के नेता राऊत ने तंज कंसते हुए कहा कि मोदी इतने नतमस्तक क्यों हुए? पहला कारण यह है कि मोदी के उद्योगपति मित्र गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में वित्तीय धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है। एपस्टीन फाइल नाम की 'फिल्म के साथ फाइल्स में भारत के बारे में काफी माल मसाला है।

मलेशिया में पीएम मोदी ने कहा- आंतक पर कोई दोहरा मापदंड नहीं और कोई समझौता नहीं

कुआलालंपुर ● एजेंसी

भारत और मलेशिया के बीच सदियों पुराने संबंधों को समकालीन वैश्विक संदर्भ में नई दिशा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिवसीय मलेशिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक रोडमैप को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी की वर्ष 2026 की यह पहली विदेश यात्रा है, जो इस क्षेत्र में भारत की प्राथमिकता और मलेशिया के साथ बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ आयोजित एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और मलेशिया की सभ्यताएं न केवल सांस्कृतिक विरासत से, बल्कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से भी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में संबंधों की गहराई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, डिजिटल

अर्थव्यवस्था और बायोटेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर, आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनानी होगी। इसके तहत खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा और काउंटर-टेररिज्म में सहयोग को और अधिक विस्तार दिया जाएगा। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया में एक नया तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सके। आर्थिक मोर्चे पर, प्रधानमंत्री ने सीईओ फोरम के माध्यम से उभर रहे निवेश के अवसरों को भारत-मलेशिया रणनीतिक बदलाव की धुरी बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि व्यापारिक बाधाएं दूर हों और आर्थिक लाभ जन-जन तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त, मलेशिया में भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास (कांसुलेट) खोलने का निर्णय दोनों देशों के बढ़ते संबंधों को प्रशासनिक मजबूती प्रदान करेगा। इस यात्रा का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण पहलू भारतीय मूल के लगभग 30 लाख प्रवासियों का उल्लेख रहा। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक जीवंत सेतु (लिविंग ब्रिज) करार देते हुए कहा कि मलेशिया, भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रवासियों की सुविधा के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मुफ्त ई-वीजा और यूपीआई डिजिटल भुगतान जैसे कदमों ने न केवल यात्रा को सुगम बनाया है, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को तकनीकी रूप से भी जोड़ दिया है। विशेष रूप से मलेशिया में तमिल समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि तमिल भाषा, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से जो सांस्कृतिक जुड़ाव बना है, उसे ऑडियो-विजुअल समझौते और तमिल फिल्मों के माध्यम से और अधिक विस्तार दिया जाएगा।

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में उम्मीदवारों ने नाबालिग बेटों से डलवाया वोट

मुंबई। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में नाबालिग को पोलिंग बूथ के अंदर ले जाने के मामले सामने आए हैं। पहला केस सोलापुर और दूसरा छत्रपति संभाजीनगर जिले से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर जिले के अकलुज स्थित यशवंत नगर मतदान केंद्र पर उम्मीदवार अर्जुन सिंह मोहिते पाटिल अपने 14 साल के बेटे के साथ पोलिंग बूथ के अंदर गए। आरोप है कि नाबालिग ने ईवीएम का बटन दबाया। वहीं छत्रपति संभाजीनगर जिले में शिवसेना विधायक अपने नाबालिग बेटे को मतदान केंद्र के अंदर ले गए। विधायक ने अपने और बेटे दोनों की उंगली पर स्याही लगवाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को राज्य के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हुए। इसमें करीब 67 फीसदी मतदान हुआ। अर्जुन सिंह मोहिते पाटिल ने कहा कि उनका बेटा केवल मतदान की प्रोसेस समझना चाहता था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यह जानना चाहता था कि वोटिंग कैसे होती है, इसलिए मैं उसे अंदर ले गया।

केंद्र सरकार ने 11 साल बाद बढ़ाई सरकारी वकीलों की फीस, मंत्रालय जारी कर चुका है अधिसूचना

नई दिल्ली ● एजेंसी

केंद्र सरकार ने अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों को बड़ी राहत देते हुए उनकी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। लगभग 11 साल बाद यह संशोधन किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 5 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के सरकारी वकीलों को अब पहले की तुलना में काफी अधिक पारिश्रमिक मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार, नियमित अपील और अंतिम सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश होने वाले 'ए श्रेणी के वकीलों को अब प्रति मामले में प्रति दिन 21,600 रुपये का भुगतान किया जाएगा। वहीं 'बी और 'सी श्रेणी के वकीलों को 14,400 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। इससे पहले 'ए श्रेणी के वकीलों को 13,500 रुपये और 'बी व 'सी श्रेणी के वकीलों को 9,000 रुपये प्रति दिन फीस मिलती थी। सरकारी वकीलों की फीस में यह संशोधन अक्टूबर 2015 के बाद पहली बार किया गया है। कानून मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी केवल नियमित अपील और अंतिम सुनवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य प्रकार के मामलों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठकों (कॉन्फ्रेंस) और सलाह-मशविरा करने की फीस में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में पेश होने वाले वकीलों की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। कानून मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, कि महंगाई, कानूनी पेशे से जुड़े बढ़ते खर्च और योग्य पेशेवरों को बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारी के अनुसार, लंबे समय से सरकारी वकीलों की ओर से फीस बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। पूर्व केंद्रीय विधि सचिव और वर्तमान में विधि आयोग की सदस्य सचिव अंजू राठी राणा ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, कि केंद्र सरकार के वकीलों के लिए फीस संशोधन की अधिसूचना अब लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान इस संबंध में निर्णय लिया गया था और यह एक दशक से अधिक समय से लंबित मामला था। उन्होंने कहा कि अदालतों में केंद्र सरकार का प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य और प्रतिभाशाली वकीलों को बनाए रखना जरूरी है।

गौरव गोगोई के कथित 'पाक कनेक्शन की होगी जांच, असम कैबिनेट ने गृह मंत्रालय को भेजी एसआईटी रिपोर्ट

नई दिल्ली ● एजेंसी

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े कथित 'पाकिस्तान कनेक्शन मामले को लेकर असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम कैबिनेट ने इस पूरे मामले को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कैबिनेट ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए केंद्र को भेजने की सिफारिश की है।मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि एसआईटी का गठन पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख की कथित भारत विरोधी साजिश की जांच के लिए किया गया था। जांच में एक सांसद और एक ब्रिटिश नागरिक के साथ कथित संपर्क और मिलीभगत के बिंदु सामने आए हैं। इसी कारण एसआईटी की रिपोर्ट और इस मामले में दर्ज एफआईआर को गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, ताकि केंद्रीय एजेंसियां विस्तृत जांच कर सकें। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पाकिस्तान से संबंध रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि गौरव गोगोई की पत्नी पहले एक ऐसे एनजीओ से जुड़ी थीं, जिनके कथित तौर पर पाकिस्तानी हितों से संबंध रहे हैं, और गोगोई स्वयं पहले पाकिस्तान जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी आरोप लगाया कि गौरव गोगोई एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान उच्चायोग गए थे, जहां उनकी मुलाकात तत्कालीन पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से हुई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि एसआईटी ने गोगोई से पूछताछ नहीं की, क्योंकि वे मौजूदा सांसद हैं और उनके पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सीधे केंद्र को मामला सौंपा गया है। सरमा ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार कठोर कदम उठाती, तो उस पर चुनाव से पहले राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगता। कैबिनेट के अनुसार यह कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि तीन प्रमुख किरदारों—एक सांसद, उनकी ब्रिटिश पत्नी और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख—से जुड़ा विषय है। एसआईटी को शेख द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में कथित दखल की जांच सौंपी गई थी और तय समय में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। वहीं दूसरी तरफ गौरव गोगोई ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें 'हास्यास्पद और बेबुनियाद बताया है। इस घटनाक्रम ने असम में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव को और तेज कर दिया है।

बॉटम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा-अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाकर शून्य किया

भारत-अमेरिका ट्रेड डील ऐतिहासिक, किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी

नई दिल्ली ● एजेंसी

भारत और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह डील ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत की नीति समझौते की है, झुकने की नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और इस समझौते में ऐसा कोई भी उत्पाद शामिल नहीं है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चौहान ने साफ किया कि भारत में किसी भी प्रकार के आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम कृषि उत्पादों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने इसे भारतीय कृषि के लिए बेहद अहम फैसला बताया और कहा कि इससे हमारी मिट्टी, हमारे बीज और कृषि की शुद्धता सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड डील में सभी संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता हमारे प्रमुख अनाजों को लेकर थी और ये सभी सुरक्षित रखे गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि अमेरिका के लिए भारत ने अपने प्रमुख अनाज, फल और डेयरी उत्पादों का कोई द्वार नहीं खोला है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं,

मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहन, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू और स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डिब्बाबंद सब्जियों को भी भारत में अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादों में भी भारत ने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं। अमेरिका से लिक्विड दूध, मिल्क पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटरमिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर और चीज को भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे भारतीय डेयरी सेक्टर और किसान परिवारों की आजीविका पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। चौहान ने कहा कि इस समझौते के तहत भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि मसालों के निर्यात में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। भारत के मसाला निर्यात में 88 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और भारतीय मसाले व मसाला उत्पाद दुनिया के 200 देशों तक पहुंच रहे हैं। 2024-25 में भारत का कुल निर्यात 4.45 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि देश को झुकने नहीं देंगे और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड डील में दोनों बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब तक 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं। अमेरिका के अलावा यूएई के 27 देश, ओमान, न्यूजीलैंड और यूके के साथ भारत एफटीए कर चुका है, जबकि अन्य देशों से बातचीत चल रही है। चौहान ने कहा कि इन सभी समझौतों का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था, किसानों, मजदूरों, गरीबों, निर्यातकों और निर्माताओं को मिलेगा और 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये मील का पत्थर साबित होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में भारत का टैरिफ अब प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले काफी कम होकर 18 फीसदी रह गया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक- नितिन श्रीवास द्वारा पंकज प्रीटर्स एड पेकिंजिंग, ए-16, एल्फा पार्क, सांवेर रोड,एल्फा इंदौर (मध्यप्रदेश) से मुद्रित 1054-एल, यूनियन बैंक, स्कीम नं. 114 इंदौर से प्रकाशित।
संपादक- नितिन श्रीवास, आर.एन.आई. नबंर - एमपीएचआईएन/20ए3002 (सभी विवादों का न्यायलय क्षेत्र इंदौर रहेगा)